मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

| वर्ष : 26 | अंक : 10 |

| जून 2026 |

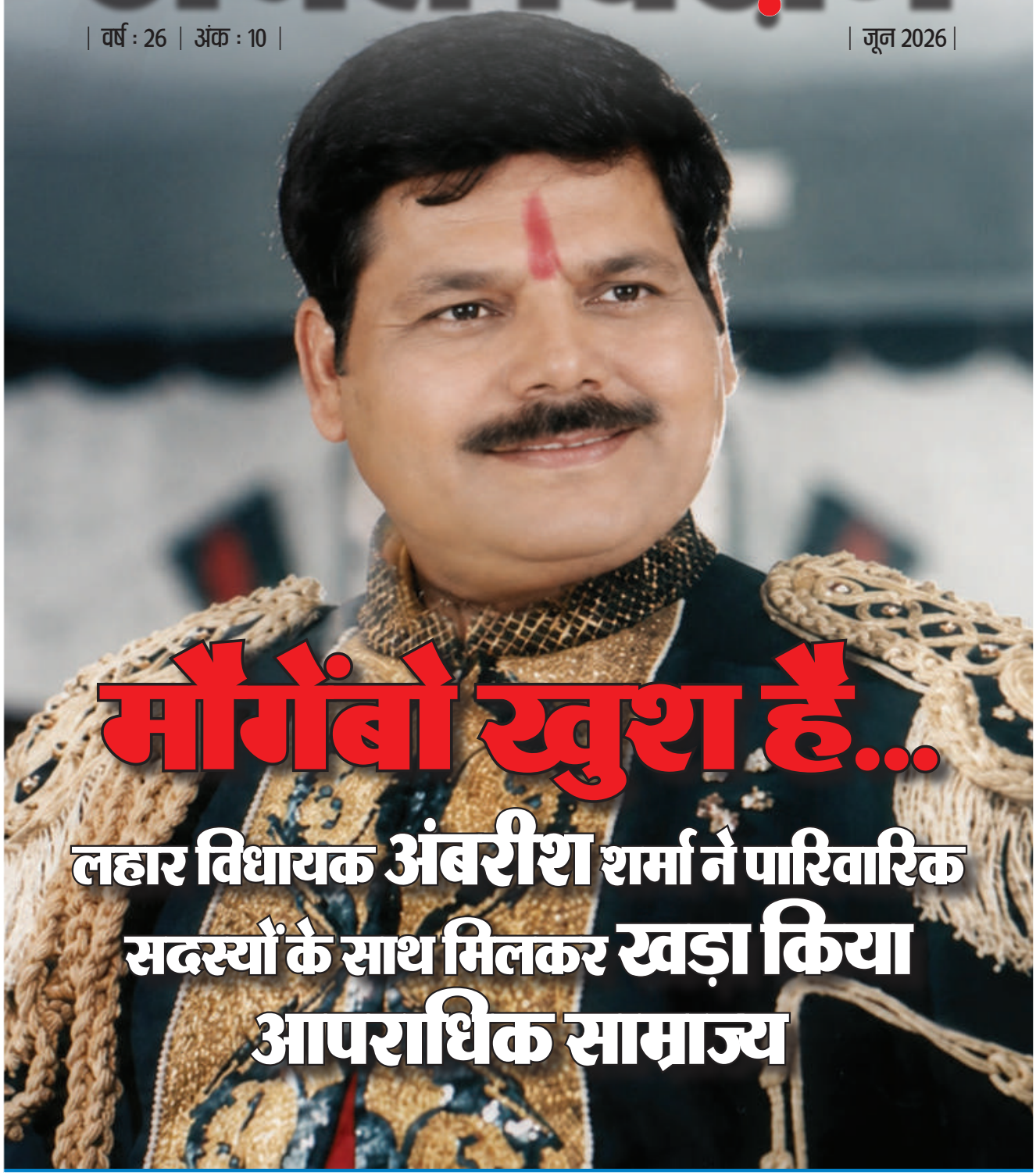

मौगैंबो खुश है...

लहार विधायक अंबरीश शर्मा ने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खड़ा किया आपराधिक साम्राज्य

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक
कार्यकारी संपादक समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक
विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

(पृष्ठ क्र.-6)

- विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए साय सरकार के ढाई साल 30
- पीएम मोदी की अपील के मायने 33
- बंगाल विजयः क्या, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिरता सहित अवैध घुसपैठ का होगा स्थायी समाधान? 44
- पीएम मोदी ने दिए संकट के संकेत 46
- कम खर्च में एक साथ चुनाव 51
- कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से अधिक सदस्य होने के निहितार्थ 55
- अमेरिका-ईरान युद्धः नई वैश्विक व्यवस्था की आहट 58
- वैभव सूर्यवंशीः भारत का उभरता क्रिकेट सितारा 61
- How Kanshi Ram's slogans became the gospel for the masses 62

ये भी किसी से कम नहीं....
विजय :)

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, विकास और जनहित की नीतियों को लागू करने का प्रमुख साधन भी है। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति अनेक महत्वपूर्ण बदलावों और चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। एक ओर देश तेजी से आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा का अनुभव कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक ध्रुवीकरण, चुनावी प्रतिस्पर्धा और सामाजिक मुद्दों पर बढ़ती बहसें लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। सरकार अपनी उपलब्धियों, विकास योजनाओं और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों को जनता के सामने रख रही है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हुए जनता से जुड़े प्रश्नों को उठाने का प्रयास कर रहा है। लोकतंत्र में यह प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, क्योंकि इससे सत्ता और विपक्ष दोनों जवाबदेह बने रहते हैं। हालांकि, कई बार यह प्रतिस्पर्धा स्वस्थ विमर्श के बजाय आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित हो जाती है, जिससे जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आज भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवा मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं और रोजगार, शिक्षा, तकनीकी विकास तथा उद्यमिता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। राजनीतिक दल भी अब युवाओं को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल अभियान और नई नीतियों का सहारा ले रहे हैं। यह परिवर्तन लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि युवा वर्ग देश की भविष्य की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सोशल मीडिया ने राजनीति की प्रकृति को काफी हद तक बदल दिया है। पहले राजनीतिक संदेशों का प्रसार मुख्यतः जनसभाओं और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से होता था, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में कोई भी राजनीतिक मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकता है। इससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, परंतु इसके साथ ही गलत सूचनाओं और भ्रामक प्रचार की समस्या भी सामने आई है। इसलिए नागरिकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे किसी भी जानकारी को सत्यापित करने के बाद ही उस पर विश्वास करें।

वर्तमान समय में आर्थिक विकास, महंगाई, रोजगार, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भारतीय राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष इन योजनाओं की प्रभावशीलता और उनके वास्तविक परिणामों पर प्रश्न उठाता है। लोकतंत्र की दृष्टि से यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नीतियों की समीक्षा होती है और बेहतर शासन की संभावना बढ़ती है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व भी लगातार बना हुआ है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों और जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति के बीच संतुलन भारतीय संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह विविधता भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को और मजबूत बनाती है।

हाल के वर्षों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की ओर संकेत करते हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से नीति-निर्माण में नए दृष्टिकोण और सामाजिक संवेदनशीलता का समावेश होता है। फिर भी भारतीय राजनीति के सामने कुछ गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं। राजनीतिक संवाद का स्तर, चुनावी खर्च, भ्रष्टाचार के आरोप, सामाजिक विभाजन और बढ़ती राजनीतिक कटुता ऐसे विषय हैं जिन पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों से नहीं, बल्कि स्वस्थ संवाद, पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों के सम्मान से सुनिश्चित होती है। अंततः, भारतीय राजनीति एक परिवर्तनशील दौर से गुजर रही है। देश के सामने विकास और लोकतंत्र को साथ लेकर आगे बढ़ने की चुनौती है। राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों सभी की जिम्मेदारी है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करें तथा राष्ट्रहित को दलगत हितों से उपर रखें।

विजया पाठक

मौगेंबो खुश है...

लहार विधायक अंबरीश शर्मा ने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खड़ा किया आपराधिक साम्राज्य

बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू करने वाले लहार विधायक अंबरीश शर्मा उर्फ गुड्डू भैया अब एक दबंग, पॉवरफुल और फर्जीवाड़ा करने वाले नेता के रूप में उभर चुके हैं। 2023 के बाद अंबरीश शर्मा ने अपने क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर अपराध तथा भ्रष्टाचार का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया है कि शर्मा एवं इनके पारिवारिक सदस्यों पर विभिन्न धाराओं के तहत 19 केस दर्ज हो चुके हैं। षड़यंत्र, धोखाधड़ी और चार सौ बीसी इनका पेशा बन चुका है। गैर कानूनी कार्यो से शर्मा ने अपना आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा कर लिया है। विधायक की शह पर इनका साला सुधांशु द्विवेदी तो इनसे चार कदम दूर निकल गया है। सुधांशु द्विवेदी ने एक फर्जी कंपनी के माध्यम से अनाज खरीदी में देश भर में कई व्यापारियों को करोड़ों का चूना लगा दिया है। अपनी दबंगई के चलते सुधांशु ने इंदौर, दिल्ली, गाजियाबाद सहित कई शहरों के व्यापारियों के करोड़ों रूपये डकार लिये हैं। जिसके अनेकों जगहों पर केस चल रहे हैं। ऐसे ही अनेकों मामलों में वह जेल की हवा भी खा चुका है। दिलचस्प तो यह है कि फर्जीवाड़े और बेईमानी के इस गोरखधंधे में विधायक की पत्नी सत्यांका शर्मा बराबर की भागीदार हैं। इन पर भी थानों में एफआईआर दर्ज है। दिल्ली में सूर्या ट्रेडिंग के नाम पर एक कंपनी है, जिसकी प्रोपराईटर विधायक की पत्नी सत्यांका शर्मा ही हैं। यह कंपनी एकदम फर्जी है। क्योंकि इस कंपनी का जो पता है वहां पर कुछ भी नहीं है। न ऑफिस है और न ही रजिस्टर्ड है। जबकि देश भर में इसी कंपनी के नाम पर वर्षो से अनाज खरीद-फरोख्त का फर्जीवाड़ा होता आ रहा है। निश्चित रूप से यह फर्जीवाड़ा बिना विधायक अंबरीश शर्मा की इजाजत से नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं विधायक की सहमति जरूर रही होगी। दूसरा सबसे बड़ा खेल इन्होंने दिल्ली में एटीएम में पैसा डालने में किया। बताया जाता है कि विधायक की एक फर्म्स को दिल्ली के विभिन्न एटीएम में पैसा डालने का काम मिला था। यह फर्म्स एटीएम में केवल 80 प्रतिशत पैसा ही डालती थी बाकी 20 प्रतिशत पैसा अपने पास रख लेती थी। लेकिन यह खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया और एक दिन इसका भंडाफोड हो गया। सूत्रों का कहना है कि इस फर्म्स को इनका साला सुधांशु द्विवेदी संभाल रहा था। बाद में जब भंडाफोड हुआ तो इनसे जुड़े कई लोगों पर एफआईआर भी हुई। इसके साथ ही 2023 के चुनाव के समय अपने हलफनामें में अंबरीश शर्मा ने जिक्र किया है कि वह दीक्षा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स के प्रोपराईटर हैं। निश्चित ही इस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स में अनेकों गाड़ियां होगी, जिनका जिक्र नहीं किया गया है। दीक्षा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स का पता भी फर्जी है। यह सच है कि लहार विधानसभा दशकों से कांग्रेस का गढ़ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी इस गढ़ को भेद नहीं पायी थी। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह कर रहे थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अंबरीश शर्मा विधायक बन गये। गोविंद सिंह को हराने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनायें गये। जब अंबरीश शर्मा ने विधायक का चुनाव लड़ा था उस समय उन पर 19 आपराधिक केस दर्ज थे। वैसे भी भिंड डाकुओं का क्षेत्र रहा है। यहां के नये नवेले नेताओं में वहीं ठसक बनी रहती है। जो ठसक आज अमरीश शर्मा में देखी जा सकती है। अब जब शर्मा को विधायकी मिली है तो वह सत्ता को पचा नहीं पा रहे हैं और अकूत संपत्ति अर्जित करने में गैरकानूनी कामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। प्रदेश में और केन्द्र में भाजपा की ही सरकार होने के कारण अंबरीश शर्मा को किसी प्रकार का डर या भय भी दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन सरकार भी सब कुछ जानते हुए अंजान बनी हुई है। और शर्मा की करतूतों और कारनामों पर पर्दा डाले हुए है। निश्चित तौर पर क्षेत्र में विधायक द्वारा लूटपाट और भ्रष्टाचार जैसे कार्यो का बुरा असर पड़ता है। और इन्हीं कारणों से अंबरीश शर्मा का काफी विरोध हो रहा है। खासकर साले और पत्नी के कारनामों के कारण तो काफी किरकिरी झेलनी पड़ रही है। क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। विधायक अपने रूतबे और दादागिरी के बल पर अनेकों क्षेत्रों में रेत का खनन कर रहे हैं। इसी अवैध रेत खनन के मामले में एक शख्स की हत्या तक हुई थी, जिससे बाद काफी बवाल मचा था। बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे वाली बात पर बदनुमा दाग लगता दिखाई देता है। जनता के बीच यह अपेक्षा बनी रहती है कि जनप्रतिनिधि और उनके परिवार सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत करें। यदि किसी भी स्तर पर पक्षपात, प्रभाव के दुरुपयोग या आर्थिक अनियमितता के आरोप लगते हैं, तो निष्पक्ष जांच होना लोकतंत्र के हित में माना जाता है। लेकिन लहार की जनता को निराशा ही हाथ लगी है। बीजेपी की सत्ता होने का पूरा लाभ विधायक अमरीश शर्मा को मिल रहा है।

बीजेपी विधायक अंबरीश शर्मा ने लहार क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण देश में गैर कानूनी कारनामों का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। बीजेपी की साख पर बट्टा लगा रहे हैं।

विजया पाठक

मध्यप्रदेश की लहार विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बीजेपी विधायक अंबरीश शर्मा गुड्डू भैया लगातार विवादों और राजनीतिक टकराव के कारण चर्चा और संघर्ष का केंद्र रही है। वे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ खुलकर बयान देते रहे हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना तक दे चुके हैं। प्रदेश में अनाज खरीदी व्यवस्था हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रही है। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान खरीदने की प्रक्रिया में अक्सर गड़बड़ी, फर्जी पंजीयन, परिवहन भुगतान और भंडारण को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लहार क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। स्थानीय राजनीति में कई बार आरोप लगाए गए कि खरीद केंद्रों पर प्रभावशाली लोगों का दबदबा रहता है और सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ मिलता है। इसी संदर्भ में विधायक अंबरीश शर्मा और उनके करीबी लोगों, जिनमें उनके साले सिधांशु द्विवेदी का नाम भी लिया जाता है। सिधांशु द्विवेदी ने अंबरीश शर्मा के साथ मिलकर अनाज खरीदी से जुड़े कुछ कार्यों में राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया है और व्यापारियों का करोड़ों रूपये का भुगतान नही किया है। वहीं बात अंबरीश शर्मा की की जाये जो वे प्रशासनिक अधिकारियों पर खुले मंच से आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं। हाल के महीनों में उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि लहार क्षेत्र की अनदेखी हो रही है और कुछ अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। लहार विधानसभा क्षेत्र में अंबरीश शर्मा ने अपनी आक्रामक राजनीतिक शैली से दबंगई की पहचान बनाई है। उनके परिवार पर प्रभाव का दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगे हैं।

लहार विधानसभा का यह क्षेत्र लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र माना

जाता रहा था। इस क्षेत्र से दशकों से पूर्व गृहमंत्री गोविंद सिंह कांग्रेस से जीतते आ रहे हैं। इसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है लेकिन 2023 के विस चुनाव में वह हार गये थे। स्थानीय लोगों का कहना रहा कि विधायक अंबरीश शर्मा के प्रभाव का लाभ उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों को मिलता है। क्षेत्र में ठेकेदारी, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों में पक्षपात होता है। इसी सक्रियता के कारण प्रशासनिक फैसलों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कई बार यह मुद्दा उठाया कि क्षेत्र में विकास कार्यों की पारदर्शिता पर सवाल हैं। आरोप लगाए गए कि कुछ ठेके और योजनाएं प्रभावशाली लोगों के पक्ष में जाती हैं। लहार क्षेत्र की राजनीति व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से भी प्रभावित रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी अक्सर सुर्खियों में रहती है।

जनता के बीच यह अपेक्षा बनी रहती है कि जनप्रतिनिधि और उनके परिवार सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत करें। यदि किसी भी स्तर पर पक्षपात, प्रभाव के दुरूपयोग या आर्थिक अनियमितता के आरोप लगते हैं, तो निष्पक्ष जांच होना लोकतंत्र के हित में माना जाता है। लेकिन लहार की जनता को निराशा ही हाथ लगी है। बीजेपी की सत्ता होने का पूरा लाभ विधायक अंबरीश शर्मा को मिल रहा है।

करोड़ों की ठगी के आरोपी सुधांशु द्विवेदी को बचा रही लहार पुलिस

भिंड जिले की लहार पुलिस अपराधियों, खनिज माफियाओं व असामाजिक तत्वों से सांठगांठ कर गरीब, शोषित, निर्दोष लोगों को परेशान करती भाजपा विधायक के साले सुधांशु द्विवेदी ने करोड़ों रूपये की ठगी की है। वह इसी आरोप में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहा था, उसे वहां से बचाने के लिये झूठे केस दर्ज कर लहार बुलाने का षडयंत्र किया गया है। अपराध क्रमांक 0087-25 करोडों रूपये लूटने वाले अपराधी सुधांशु द्विवेदी जिस पर दिल्ली, बिहार, उत्तरप्रदेश, मप्र के इन्दौर सहित लगभग 125 करोड़ रूपयों की व्यापारियों के साथ धोखाधडी कर लूटने के अपराध में मुम्बई की आर्थर जेल में बन्द था। अपराध मुम्बई की क्राइम ब्रान्च एवं ईडी द्वारा दर्ज कराया था। थाना लहार द्वारा सुधांशु द्विवेदी को बचाने के लिए जेल में

दबंगई का दूसरा नाम अंबरीश शर्मा है। अपने लाव लश्कर के साथ चलने वाले विधायक खुद के साथ अपने परिजनों को भी शह देते हैं। यही कारण है कि अवैध गोरखधंधों का पूरे देश में मकड़जाल फैला दिया है। साले सुधांशु द्विवेदी और पत्नि सत्यांका शर्मा को भी हिस्सेदार बनाया। ऐसे जनप्रतिनिधि के भरोसे बीजेपी अपनी विकास की राजनीति कर रही है।

रहते हुए माह अक्टूबर 2024 की पुरानी तारीख में आवेदन प्राप्त कर इन्दौर के निवासी 4 गरीब मजदूर तथा एक छोटे व्यापारी अतुल सोनी पर असत्य अपराध दिनांक 02.05.2025 को लहार थाने में दर्ज कर दिनांक 14.05.2025 को दो लोगों

इंदौर के कारोबारी गुरूजीत सिंह छाबड़ा से विधायक अंबरीश शर्मा के साले सुधांशु द्विवेदी ने की 97 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी

अनाज के लिए 452 करोड़ का भुगतान किया, केवल 355 करोड़ की आपूर्ति मिली

इंदौर के कारोबारी गुरूजीत सिंह छाबड़ा से विधायक अमरीश शर्मा के साले सुधांशु द्विवेदी ने की 97 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी की है। विधायक शर्मा की सरफरस्ती में ही यह धोखाधड़ी हुई है। निश्चित ही इस रकम का बड़ा हिस्सा विधायक के पास पहुंचा होगा। सही मायने में इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाईंड अंबरीश शर्मा ही हैं। क्योंकि अनाज के ट्रांसपोर्ट में जो वाहन उपयोग हुए हैं वह विधायक की ट्रांपपोर्ट कंपनी के ही थे। दरअसल मामला इस प्रकार है- इंदौर के व्यापारी गुरूजीत सिंह छाबड़ा की सुधांशु द्विवेदी से मुंबई बांद्रा के एक 05 सितारा होटल में आयुष सूद नाम के एक व्यक्तिके जरिए मुलाकात हुई थी। द्विवेदी ने खुद को कमोडिटी के तौर पर परिचय दिया था। सुधांशु द्विवेदी ने छाबड़ा को बताया कि वह किसानों से सीधे अनाज खरीदता है और उन्हें विभिन्न व्यापारियों को सप्लाई करता है। उसने दावा किया कि इस निवेश

विधायक अंबरीश शर्मा और उनका साला सुधांशु द्विवेदी

को इन्दौर से गिरफ्तार कर लहार जेल में डलवा दिया है। विभिन्न आरोपों में घिरे व करोड़ों रूपये ठगने वाले आरोपी सुधांशु द्विवेदी को मध्यप्रदेश पुलिस ने सुरक्षा पीएसओसी उपलब्ध कराये। अपराध क्रमांक 0155/2025 में पुलिस ने

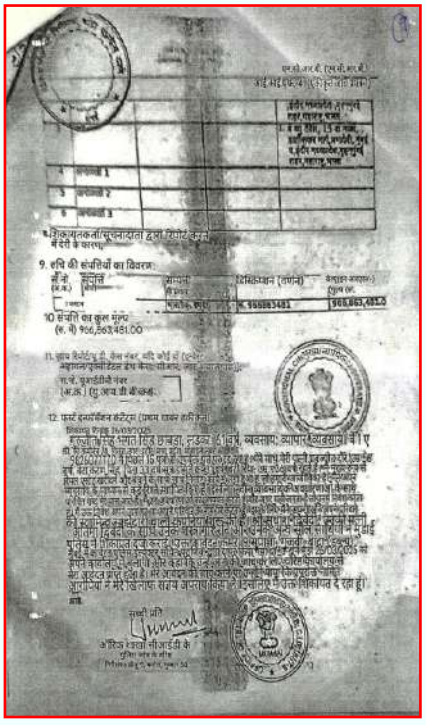

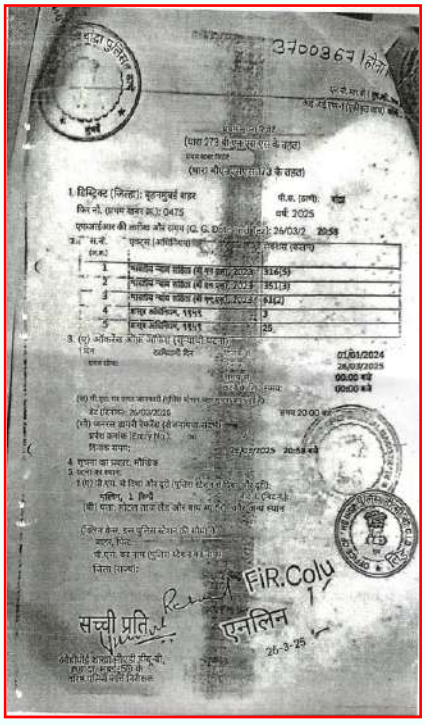

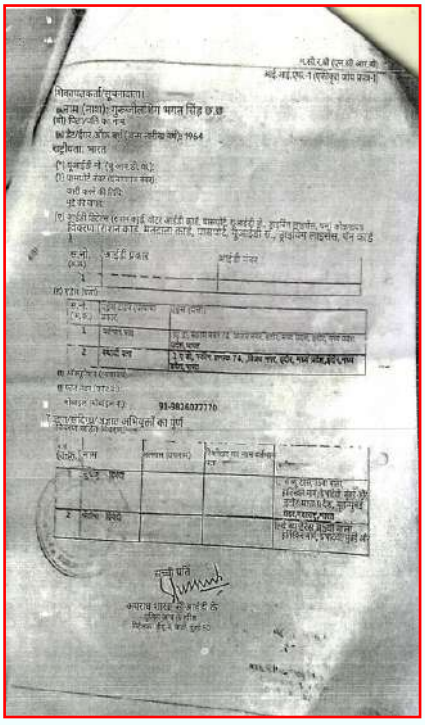

यह एफआईआर की वह कापियां है जो गुरूजीत सिंह छाबड़ा ने अंबरीश शर्मा के साले सुधांशु द्विवेदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

में बहुत ज्यादा मुनाफा है। छाबड़ा, द्विवेदी के प्रस्ताव से आकर्षित हुए और उन्होंने निवेश करने का फैसला किया। छाबड़ा ने द्विवेदी के बैंक खाते में अग्रिम राशि के रूप में 05 करोड़ रूपये हस्तांतरित किए और एक ऑर्डर दिया। छाबड़ा ने पुलिस को बताया था कि द्विवेदी के अनुरोध पर आशा ओवरसीज इंडिया के कंपनी खाते में 340 करोड़ रूपये और गणेश एंटरप्राइजेज में 91.19 करोड़ रूपये हस्तांतरित किए, जो कुल 452 करोड़ रूपये की राशि थी। छाबड़ा ने आरोप लगाया कि द्विवेदी ने उन्हें 355 करोड़ रूपये का अनाज सप्लाई किया था। जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो छाबड़ा, द्विवेदी के प्रभादेवी स्थित फ्लैट पर गए, जहां कुछ हथियारबंद गुंडों ने उन्हें बंधक बना लिया। द्विवेदी ने धमकी भी दी कि अगर उन्होंने दोबारा यह मुद्दा उठाया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने सुधांशु को और उसके कर्मचारी रवि गुप्ता को 97 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने तथा पूछताछ करने पर हथियार से धमकाने के आरोप में धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार

पुलिस ने सुधांशु को और उसके कर्मचारी रवि गुप्ता को 97 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने तथा पूछताछ करने पर हथियार से धमकाने के आरोप में धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

बलात्कार का फर्जी केस दर्ज कर सिर्फ इसीलिए सुधांशु द्विवेदी और उसके साथी रवि गुप्ता को मुंबई से लहार लाने की कोशिश की ताकि उन्हें वहां सुविधाएं दी जा सकें। यह सब आरोपी के रिश्तेदारों से मिलीभगत कर किया गया।

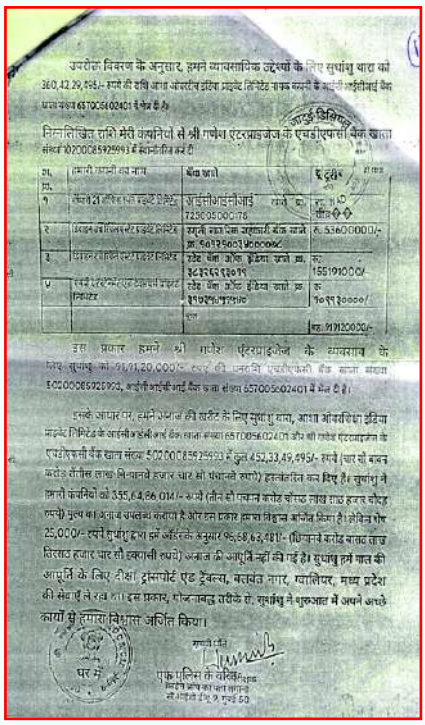

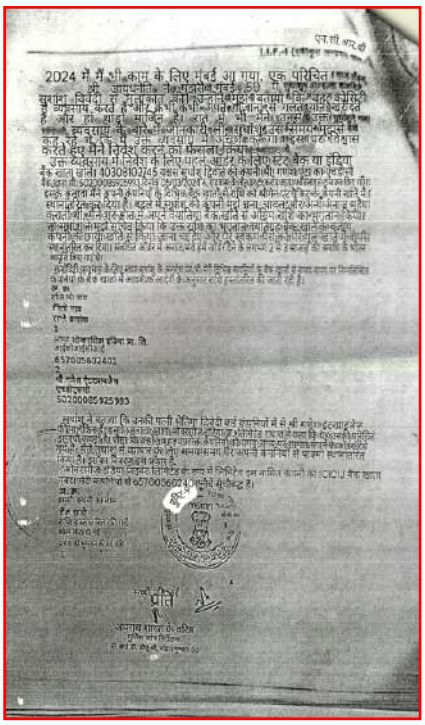

इस एफआईआर में छाबड़ा ने सम्पूर्ण ब्योरे का जिक्र किया है।

किया था। गुरूजीत सिंह भगत सिंह छाबड़ा ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में आरोपी सुधांशु द्विवेदी, उनकी पत्नी श्रेतिमा द्विवेदी और उनके कर्मचारी रवि और उनके तीन अन्य साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अभियुक्तों ने संज्ञेय अपराध किया है। इसलिए, वादी का बयान दर्ज किया गया और बांद्रा पुलिस स्टेशन में जी.आर.नंबर 475/25 धारा 316 (5), 351 (3), 61 (2) भारतीय न्यायिक संहिता के साथ धारा 3, 25 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त

गुरूजीत सिंह भगत सिंह छाबड़ा ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में आरोपी सुधांशु द्विवेदी, उनकी पत्नी श्रेतिमा द्विवेदी और उनके कर्मचारी रवि और उनके तीन अन्य साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

प्रकरण कक्ष 9, गु.प्र.से. में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे की जांच के लिए कक्षाएँ जी.ए.वी., बांदा में आयोजित की गईं। उक्त अपराध को अपराध शाखा में जी.आर.नं. 21/2025 के तहत पुनः दर्ज किया गया था। एफ न्यायिक आरोपी नं. 1 सुधांशु द्विवेदी, उनकी कंपनी के साथ-साथ उक्त कंपनी की मालिक श्रेतिमा द्विवेदी, उनके कर्मचारी रवि गुप्ता (अभियुक्त नंबर 02) और उसके अन्य सहयोगियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर पहले लेन-देन के माध्यम से वादी का विश्वास हासिल

इनामी अपराधी खुलेआम में घूम रहे

लहार पुलिस ने आर्थर जेल मुम्बई में बंद ठगी के आरोपी सुधांशु द्विवेदी एवं रवि गुप्ता के रिश्तेदारों से मिलकर षडयंत्र रचकर आरोपी सुधांशु द्विवेदी एवं रवि गुप्ता को लहार जेल में बुलाने हेतु, जिससे उसे

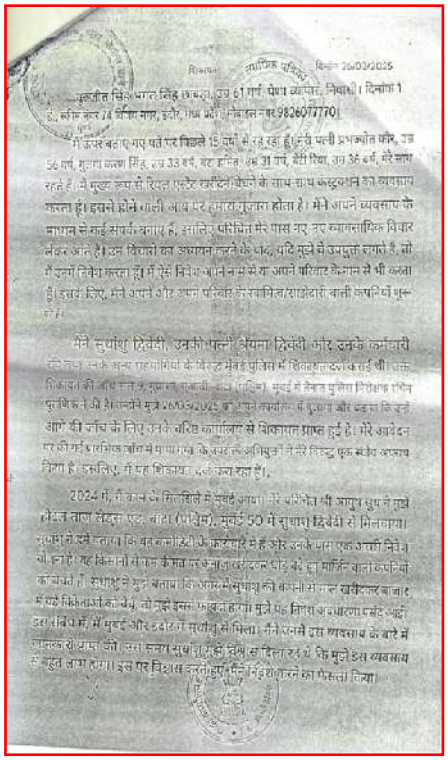

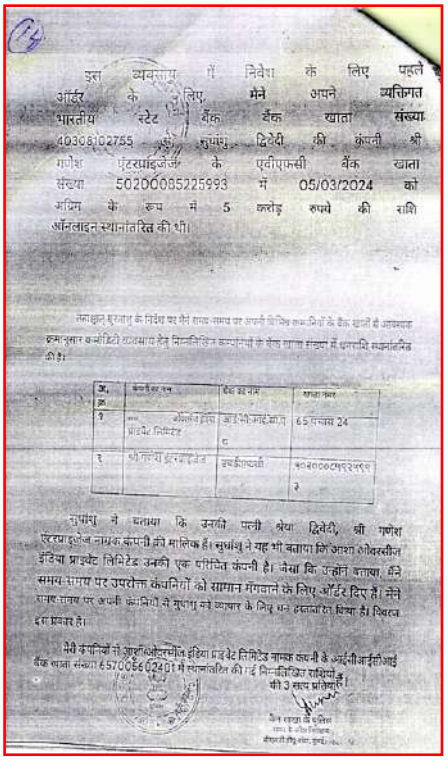

किया और फिर बदले में रुपये की मांग की। उन्हें वस्तुओं के रूप में सामान न देकर उनके साथ अन्याय किया गया है। जब वादी उक्त रकम व सामान मांगने गया तो अभियुक्त सुधांशु, उसकी पत्नी के साथ-साथ रवि गुप्ता और उसके साथियों ने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाकर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने अभियोजकों को डरा दिया। इसलिए वादी ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई।

मामले का लेखा-जोखा: इस बैंक खाते में 01/03/20 को एक करोड़ रूपये की रकम एडवांस के रूप में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। सुधांशु द्विवेदी को ऑर्डर देने के लगभग 2 से 3 दिन में ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। संबंधित ऑर्डर का माल/सामान सप्लाई कर दिया गया। उससे सुधांशु द्विवेदी गायब हो गया। इसके बाद छाबड़ा ने अपने विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सुधांशु द्विवेदी को ओहरशिक्षा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर। लिमिटेड इस नामित कंपनी का आईसीआईसीआई बैंक खाता नंबर 657001602401 वावर 360,42,29,495/- (तीन सौ साठ करोड़ बयालीस लाख उनतीस हजार चार सौ पंचानवे) हस्तांतरित किये गये। वहीं श्री गणेश इंटरप्राइजेज का एचडीएफसी बैंक खाता नंबर 50200085925993 जिसमें से रूपये 91,91,20,000/- (इक्यानबे करोड़ एक लाख बीस हजार) हस्तांतरित किये गये। दोनों खातों की कुल रकम के हिसाब से अनाज खरीद हेतु 452,33,49,495/- (चार सौ बावन करोड़ तीन लाख उनचास हजार चार सौ उनचास रु पये) हस्तांतरित किये गये हैं। इनमें सुधांशु द्विवेदी ने 355,64,86,014/- (तीन सौ पचपन करोड़ बासठ लाख अस्सी हजार चौदह रूपये) की धनराशि से छाबड़ा की कम्पनियों को अनाज उपलब्ध कराया। लेकिन शेष इस अनाज की राशि 96,68,63,481/- (छियानवे करोड़ बासठ लाख तीन सौ इक्यासी रूपये) उपलब्ध नहीं कराया है। सुधांशु द्विवेदी की पत्नी श्रेतिमा द्विवेदी ने धमकी दी कि उसके बड़े राजनेताओं से संबंध है और उनकी मदद से छाबड़ा के अन्य व्यवसायों में बाधा डालेगी। छाबड़ा को डर था कि अगर वह उसके खिलाफ शिकायत करेगा तो उसको नुकसान होगा। इसके बाद छाबड़ा ने सुधांशु द्विवेदी और दूसरों के विरूद्ध शिकायत करने का साहस नहीं किया। इसके बाद वे इंदौर के लिए रवाना हो गये।

सुख सुविधायें प्रदान की जा सके। बलात्कार जैसा संगीन असत्य अपराध दर्ज कर मुम्बई जेल से दोनों अपराधियों को लहार लाने में सफलता प्राप्त कर ली है।

भिंड में सत्ता, संरक्षण और विवादों के केंद्र बने मंत्री राकेश शुक्ला

विधायक अमरीश शर्मा ने चुनावी हलफनामें में छुपाई कई अहम जानकारियां

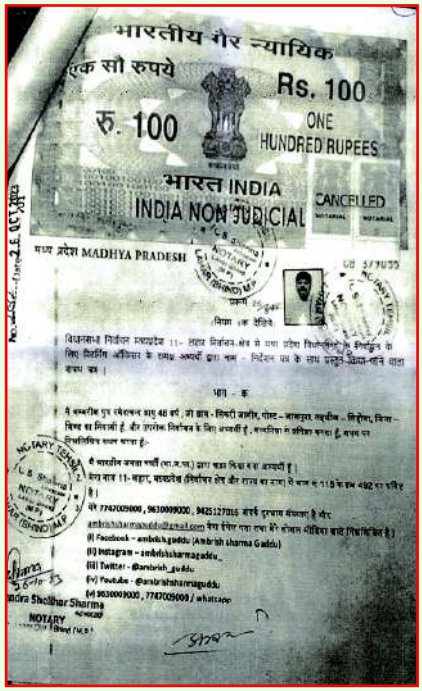

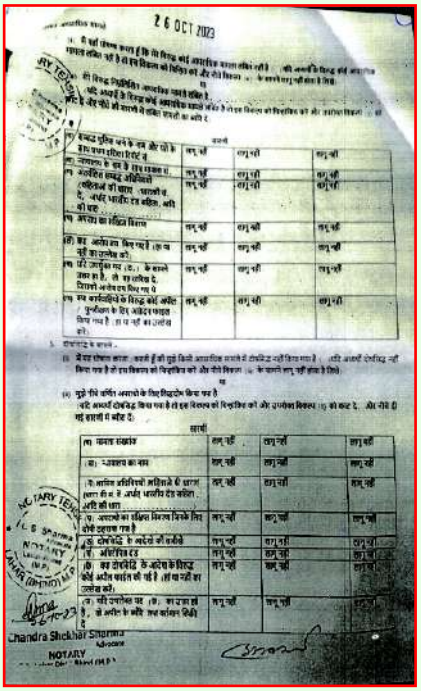

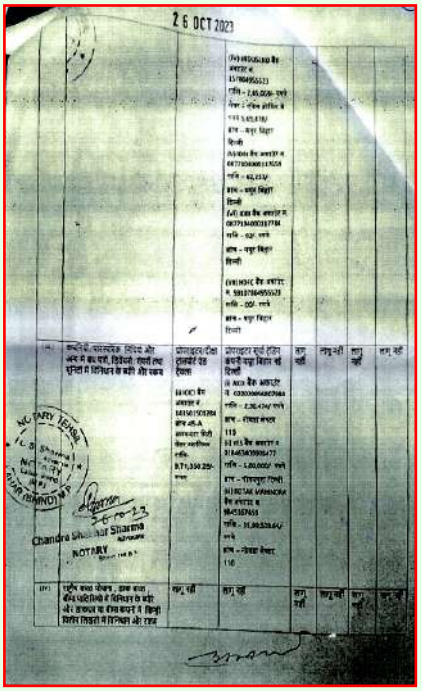

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी विधायक अंबरीश शर्मा ने अपने चुनावी हलफनामें में कई अहम जानकारियां छुपाई। जैसे सूत्रों का कहाना है कि जब अंबरीश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे उस समय विभिन्न थानों से उन पर 19 आपराधिक मामले दर्ज थे। जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा उनके नाम से दीक्षा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स नाम की एजेंसी है। वही पत्नि के नाम पर नई दिल्ली में सूर्या ट्रेडिंग कंपनी दर्शाई गई थी। बाद में इन्हीं कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी और गोरखधंधे की वारदातों को अंजाम दिया गया। जिसकी एफआईआर तक हुई। उपरोक्त दस्तावेज हलफनामें की कापियां है। सूत्रों का मानना है कि विधायक ने अपनी चल-अचल संपत्ति के विषय में भी गलत जानकारियां दी थी। अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा नहीं बताया था। आज की स्थिति में इनकी संपत्ति करोड़ो रूपये में है।

मध्यप्रदेश की राजनीति में समय-समय पर ऐसे प्रसंग सामने आते रहे हैं, जब सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इन दिनों प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला को लेकर भिंड जिले से जिस प्रकार की चर्चाएं और आरोप

क्षेत्र में फैला विधायक अंबरीश शर्मा का आतंक

यह कवर स्टोरी करने के पहले जगत विजन की टीम ने भिण्ड जिले की लहार विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। स्थानीय लोगों से और स्थानीय राजनेताओं से अन्य आवश्यक मुद्दों के अलावा यहां के बीजेपी विधायक अंबरीश शर्मा के विषय में जाना और समझा। बातचीत में कई चौकाने वाले वाकये सामने आये। विधायक की गुण्डागर्दी, दबंगई और भ्रष्टाचार जैसे कई मामलों पर लोगों ने खुलकर बात की। लोगों ने अवैध रेत उत्खनन, विधायक के परिजनों द्वारा सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जा, फर्जी फर्म के जरिये लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, सरकारी ठेकों में अपनी मनमर्जी चलाना, शासन-प्रशासन में दबंगई दिखाना जैसे अनेकों कारनामों का जिक्र किया। ऐसे बहुत कम लोग या राजनेता थे जो विधायक अंबरीश शर्मा के कामों से खुश थे। सभी ने उनके सत्ता के रसूख के किस्से सुनाये। अपने ढाई साल के कार्यकाल में विधायक ने आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा किया है। अनेकों जगहों पर उनकी जमीनें हैं। कई ठेकों में हिस्सेदारी है। दिलचस्प तो ये है कि विधायक के इस पूरे गोरखधंधे में उनके साले सुधांशु द्विवेदी और पत्नी सत्यांका शर्मा भी बराबर की हिस्सेदार रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे गोविंद सिंह के कार्यकालों को बेहतर बताया। लोगों का कहना था कि गोविंद सिंह के समय क्षेत्र में ऐसा आतंक नहीं होता था। वह लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। क्षेत्र के विकास पर फोकस करते थे। लेकिन इस समय तो केवल विधायक जी का ही विकास हो रहा है।

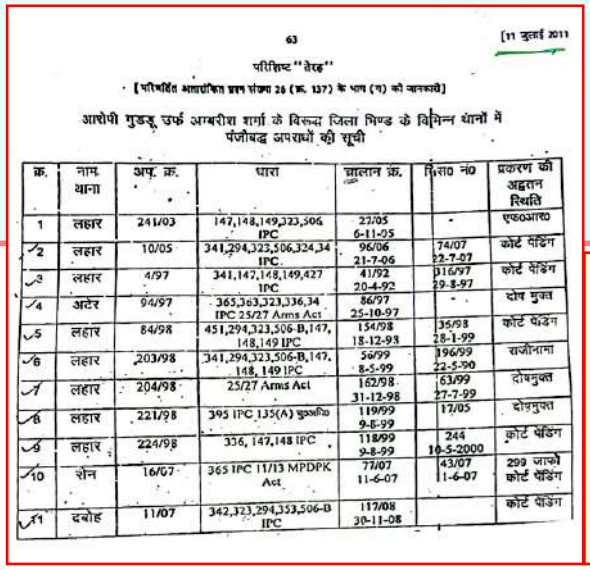

63 [11 जुलाई 2011

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 137) के भाग (ग) की जानकारी]

आरोपी गुड्डू उर्फ अम्बरीश शर्मा के विरूद्ध जिला भिण्ड के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध अपराधों की सूची

क्र.	नाम थाना	अप. क्र.	धारा	चालान क्र.	फि0स0 नं0	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
1	लहार	241/03	147,148,149,323,506 IPC	27/05 6-11-05	-	एफ0आर0
2	लहार	10/05	341,294,323,506,324,34 IPC	96/06 21-7-06	74/07 22-7-07	कोर्ट पेंडिंग
3	लहार	4/97	341,147,148,149,427 IPC	41/92 20-4-92	316/97 29-8-97	कोर्ट पेंडिंग
4	अटेर	94/97	365,363,323,336,34 IPC 25/27 Arms Act	86/97 25-10-97	-	दोष मुक्त
5	लहार	84/98	451,294,323,506-B,147, 148,149 IPC	154/98 18-12-98	35/98 28-1-99	कोर्ट पेंडिंग
6	लहार	203/98	341,294,323,506-B,147, 148, 149 IPC	56/99 8-5-99	196/99 22-5-90	राजीनामा
7	लहार	204/98	25/27 Arms Act	162/98 31-12-98	63/99 27-7-99	दोषमुक्त
8	लहार	221/98	395 IPC 135(A) [illegible]	119/99 9-8-99	17/05	दोषमुक्त
9	लहार	224/98	336, 147,148 IPC	118/99 9-8-99	244 10-5-2000	कोर्ट पेंडिंग
10	रौन	16/07	365 IPC 11/13 MPDPK Act	77/07 11-6-07	43/07 11-6-07	299 जाफो कोर्ट पेंडिंग
11	दबोह	11/07	342,323,294,353,506-B IPC	117/08 30-11-08		कोर्ट पेंडिंग

भिण्ड जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विधायक अंबरीश शर्मा पर दर्जनों प्रकरण दर्ज है

सामने आ रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री का पद केवल सत्ता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि वह जवाबदेही, नैतिकता और जनविश्वास का भी दायित्व लेकर चलता है। ऐसे में यदि किसी मंत्री के नाम के साथ अवैध खनन,

एटीएम में पैसे डालने में हेराफेरी

20 अगस्त 2020 को राजेश सांगवान, सीओ एसआईएस कैश सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बी-26, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली, ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि एसआईएस प्रॉसेगुर विभिन्न बैंकों को एटीएम में नकदी भरने के लिए नकदी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में कंपनी बैंकों से नकदी निकालती है और एमएसपी (प्रबंधित सेवा प्रदाता) बैंकों द्वारा दिए गए इंडेंट के अनुसार एटीएम में नकदी भरती है। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 अगस्त 2020 को उनके ऑडिटर भगत सिंह ने आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम रूट नंबर 011-708 के एटीएम का ऑडिट किया और आईसीआईसीआई बैंक के छह एटीएम में 20,07,300 रूपये की कमी पाई। भिंड के अनुराग सिंह और उमरिया जिले के वीरेंद्र सिंह मरावी को आईसीआईसीआई बैंक के रूट 011-708 के लिए जिम्मेदार माना गया। जांच में दोनों कस्टोडियन से पूछताछ की गई और अनुराग सिंह ने स्वीकार किया कि उसने 20,07,300 रुपये की बकाया राशि की चोरी/गबन की है। उपरोक्त शिकायत पर ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 391/2020, धारा 408/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान अनुराग सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। अनुराग सिंह ने खुलासा किया कि उसे उसके मित्र विनय झा ने उकसाया था, जो वर्तमान में भिंड जिले के लहार थाना में रहता है। विनय झा ने उससे नकदी चुराने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि अगर वह उसे (विनय झा को) नकदी दे तो वह उसे दुगुने मुनाफे के साथ लौटा देगा। विनय झा के उकसावे पर उसने कंपनी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार एटीएम में नकदी जमा नहीं की और नकदी अपने पास रख ली। उसने आगे खुलासा किया कि उसने पिछले 20 दिनों के दौरान अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से विनय झा को लगभग 17.5 लाख रूपये और उसके सहयोगी को 80 हजार रूपये दिए थे और खाताधारक अलग-अलग हैं। अनुराग सिंह ने कई अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश रचते हुए 20,07,300 रुपये की भारी रकम का गबन किया, जो उसे सौंपी गई थी। अनुराग सिंह के सहयोगी और उसके सभी साथियों के कब्जे से केवल 7,57,000 रूपये ही बरामद किए गए हैं और गबन की गई राशि का बड़ा हिस्सा अभी बरामद होना बाकी है। इस मामले में सह-आरोपी विनय झा, रवि प्रजापति अंबरीश शर्मा और सत्येंद्र को गिरफ्तार नहीं किया गया।

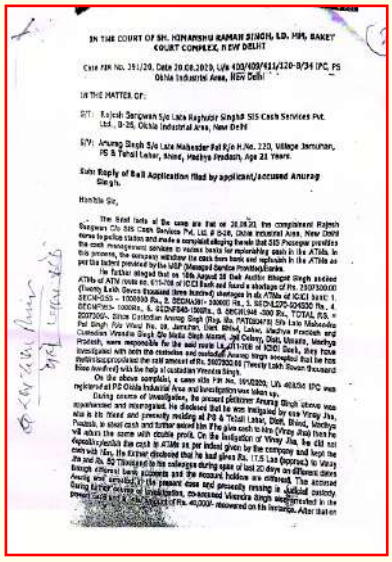

IN THE COURT OF SH. HIMANSHU RAMAN SINGH, LD. MM, SAKET COURT COMPLEX, NEW DELHI

Case FIR No. 391/20, Date 20.08.2020, U/s 408/409/411/120-B/34 IPC, PS Okhla Industrial Area, New Delhi

IN THE MATTER OF:

S/T: Rajesh Sangwan S/o Late Raghubir Singh SIS Cash Services Pvt. Ltd., B-26, Okhla Industrial Area, New Delhi

S/V: Anurag Singh S/o Late Mahender Pal R/o H.No. 220, Village Jamunan, PS & Tehsil Lahar, Bhind, Madhya Pradesh, Age 21 Years.

Sub: Reply of Bail Application filed by applicant/accused Anurag Singh.

Hon'ble Sir,

[illegible]

-3-

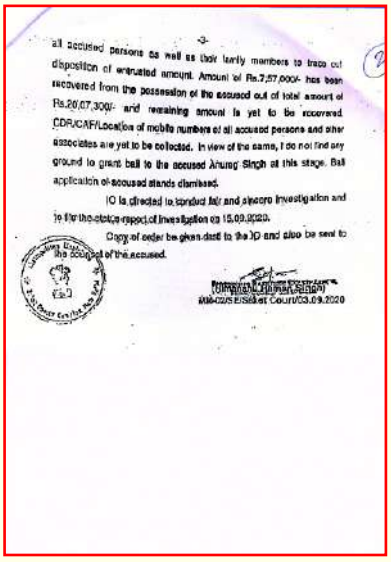

all accused persons as well as their family members to trace out disposition of entrusted amount. Amount of Rs.7,57,000/- has been recovered from the possession of the accused out of total amount of Rs.20,07,300/- and remaining amount is yet to be recovered. CDR/CAF/Location of mobile numbers of all accused persons and other associates are yet to be collected. In view of the same, I do not find any ground to grant bail to the accused Anurag Singh at this stage. Bail application of accused stands dismissed.

IO is directed to conduct fair and sincere investigation and to file the status report of investigation on 15.09.2020.

Copy of order be given dasti to the IO and also be sent to the counsel of the accused.

(Himanshu Raman Singh)
MM-02/SE/Saket Court/03.09.2020

प्रशासनिक हस्तक्षेप और असामाजिक तत्वों को संरक्षण जैसे आरोप जुड़ने लगें, तो यह केवल एक व्यक्तिका मामला नहीं रह जाता, बल्कि शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह बन जाता है।

लहार क्षेत्र में विधायक की शह पर धड़ल्ले से चल रहा रेत का अवैध कारोबार

रेत माफियाओं ने कुचल दिया घर के एकलौते चिराग को

लहार के विधायक अंबरीश शर्मा की शह पर क्षेत्र में रेत खदानों पर अवैध रेत खनन का कार्य चल रहा है। शासन ध्यान नहीं दे रहा है। अब रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में भी दौड़ रहे हैं रेत से भरे ट्रक और ट्रैक्टर। लहार विधानसभा क्षेत्र में सिंध नदी के तटीय इलाकों- विशेषकर पर्रायच और असवार क्षेत्रों में रेत का अवैध खनन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 02 फरवरी 2025 को पवन सिंह उर्म 24 वर्ष जो अपना खाली ट्रेक्टर कृषि कार्य करके घर लेकर जा रहा था, तब ही उसे पकड़ने के लिए रेतमाफियाओं के साथ पुलिस भेजकर पवन सिंह को पकड़ने के लिए पीछा किया गया। डर के कारण पवन सिंह का ट्रेक्टर पलट गया और उसकी मृत्यू हो गई। इस घटना के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने 03 फरवरी 2025 को मछण्ड चौकी का घेराव किया और दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग की। रेतमाफियाओं के कारण घर का एकलौता चिराग पवन सिंह बुझ गया।

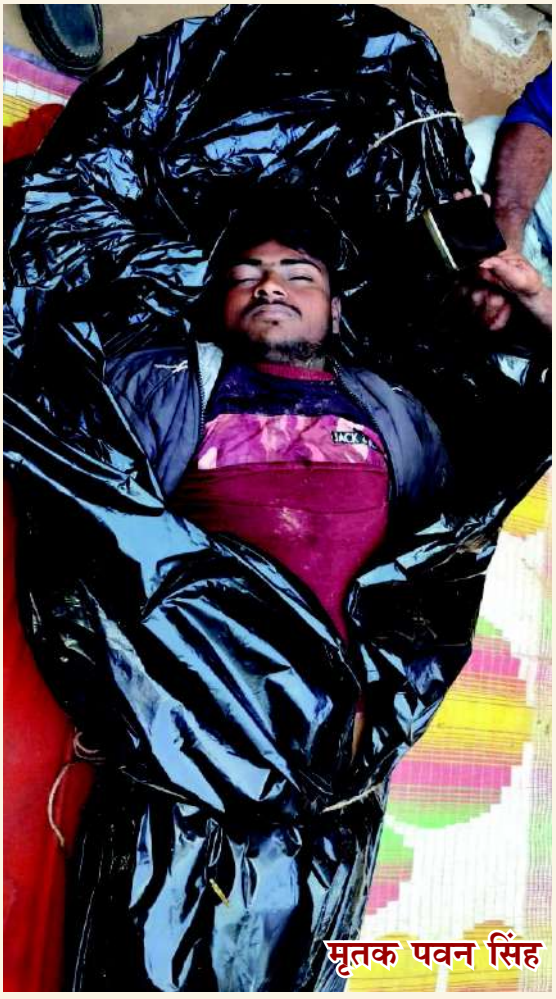
मृतक पवन सिंह

पवन सिंह की माँ को घर में घुस कर पीटा

पवन सिंह की माँ बिन्दुश्री ने मछण्ड चौकी प्रभारी रविन्द्र सिंह पर मारपीट के आरोप लगाये थे। उनके बेटे की ट्रेक्टर खाई में गिरने से हुई मौत का केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने, गवाहों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने तथा जेल भेजने जैसे बाते शामिल थी। इस मारपीट में बिन्दुश्री को काफी चोटें आई थी। जिनका एक माह तक ग्वालियर में इलाज हुआ। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और आखिर में चौकी प्रभारी को लाईन अटैच किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना पर उतरे शुक्ला

भिंड और चंबल क्षेत्र लंबे समय से रेत खनन और उससे जुड़े विवादों के कारण चर्चा में रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय

एनजीटी की रोक और प्रशासन के दावों के बावजूद रेत माफिया अक्सर सिंध नदी का सीना चीरकर अवैध उत्खनन करते हैं। इस क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान कई बार ट्रैक्टर और ट्रक सिंध नदी के बीचों-बीच रेत में फंस चुके हैं, जिससे अवैध उत्खनन के बड़े पैमाने का खुलासा हुआ है। एक तरफ प्रशासन सिंध नदी से अवैध उत्खनन की बात को नकारता आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नदी से रेत का उत्खनन चरम पर है। 30 जून से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर नदियों से रेत उत्खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन भिंड जिले में रेत माफिया एनजीटी के आदेश को धता बताकर अवैध उत्खनन किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब नदी से रेत उत्खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है तो दिन दहाड़े अवैध उत्खनन कैसे हो रहा है। जिला प्रशासन या पुलिस को अवैध खनन और परिवहन करते ट्रक आखिर क्यों नजर नहीं आ रहे हैं।

पवन सिंह की मॉ बिन्दुश्री

माफिया-प्रशासन की मिली भगत से ठेका कंपनी को नुकसान

भिंड जिले में रेत खनन का टेंडर नई ठेका कंपनी शिवा कॉर्पोरेशन को मिला है लेकिन काम शुरू होते ही बारिश के सीजन को देखते हुए नदी से रेत उत्खनन पर एनजीटी ने रोक लगा दी। जिसकी वजह से रेत कंपनी को काम करने का मौका नहीं मिला और माफिया ने इसका फायदा उठाते हुए सिंध का दोहन शुरू कर दिया। 2019 में भी ठेका कंपनी पॉवरमेक ने भी रेत माफिया और जिला प्रशासन की मिलीभगत के चलते हो रहे नुकसान की वजह से रेत का ठेका सरेंडर किया था।

सवालों के घेरे में जिला प्रशासन

भिंड पुलिस और जिला प्रशासन की मिली भगत और अनदेखी अब सवालों के घेरे में है। भिंड में अवैध खनन कर रेत उत्तर प्रदेश में बेची जा रही है। इससे ना सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि गलत तरीके से अवैध खनन पर नदियों को भी नुकसान हो रहा है। भिंड से होकर बहने वाली सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। यहां दो साल से रेत खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते सभी सरकारी ठेके ठप पड़े हैं। जून 2023 से किसी के पास भी रेत निकालने की कानूनी अनुमति नहीं है। 11 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम ने भिंड में 72 रेत खदानों के ठेके आरएसआई स्टोन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड और नर्मदा माइनिंग एंड मिनरल्स को दिए। इन ठेकों की कुल कीमत 55.35 करोड़ रूपये थी। हालांकि, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने काम पर रोक लगा दी है, जिससे खनन कार्य निलंबित है।

पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद यदि अवैध खनन के आरोप लगातार सामने आते हैं, तो यह प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि मंत्री राकेश शुक्ला के प्रभाव के कारण प्रशासन कई

विधायक अंबरीश शर्मा बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं से मिलकर बढ़ाते हैं अपना रूतबा

मामलों में दबाव में कार्य करने को मजबूर दिखाई देता है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन को कानून और संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दबाव के

लहार भाजपा विधायक अंबरीश शर्मा के साले सुधांशु द्विवेदी पर लगा धोखाधड़ी का केस

सूर्या ट्रेडिंग पर आरोप, विधायक की पत्नी सत्यांका शर्मा का भी नाम

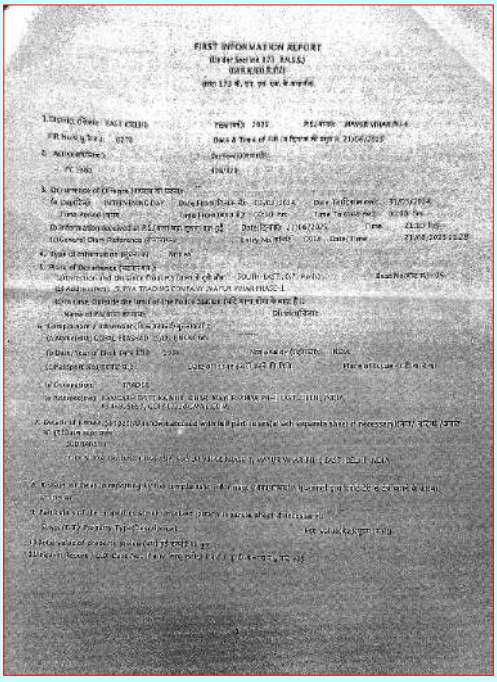
FIRST INFORMATION REPORT

ईडी और बलात्कार की एफआईआर में जेल में बंद रहे भाजपा के लहार विधायक अंबरीश शर्मा के साले सुधांशु द्विवेदी की मुश्किलें तब बढ़ गई जब दिल्ली में दर्ज धोखाधड़ी की एक और एफआईआर सामने आई थी। विधायक के साले पर 02 करोड़ रूपए न देने का आरोप हैं। यह एफआईआर ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार थाने में दर्ज हुई थी। इसमें बिहार के रहने वाले गोपाल प्रसाद ने शिकायत की थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह चावल व्यवसायी है। उनका सूर्या ट्रेडिंग कंपनी से लेनदेन चलता था। यह कार्य कंपनी की प्रो. सत्यांका शर्मा के भाई सुधांशु द्विवेदी करते थे। करीब डेढ़ साल तक इनसे लेनदेन ठीक चला। इसके बाद सुधांशु से जब 02 करोड़ 25 लाख रूपए लेने थे, तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। काफी प्रयास करने पर 25 लाख रुपए भेज दिए। इसके बाद 02 करोड़ रूपए नहीं दिए हैं। पुलिस ने सुधांशु के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले सुधांशु के खिलाफ मुंबई में ईडी मामला दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा लहार में एक महिला ने भी एफआईआर कराई थी।

आधार पर।

प्रशासन पर हावी है शुक्ला का रौब

सबसे अधिक चिंता का विषय प्रशासनिक ढांचे में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। भिंड जिले में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में मंत्री की

विधायक अंबरीश शर्मा को 03 सरकारी आवास आवंटित

विधायक अंबरीश शर्मा सिर्फ अपने क्षेत्र में रसूख और दबंगई के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि शासन प्रशासन में भी उनकी धाक धड़ल्ले से चल रही है। वैसे तो विधायक को राजधानी में एक सरकारी आवास आवंटित करने का नियम है। लेकिन अंबरीश शर्मा इन नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए अपने पास 03 सरकारी आवास आवंटित किये हुये है। जिनमें एक सरकारी आवास डी-22, मालरोड 07 नम्बर चौराहे के पास, मुरार रोड, ग्वालियर, दूसरा राजधानी स्थित विश्राम गृह, खण्ड-3 में 18, 19, 82 आवास आवंटित है। जबकि तीसरा आवास लहार स्थित जनपद पंचायत का बंगला है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लहार के निवास के विरूद्ध आवंटित किया गया है। इस निवास को मोडिफाईड कराकर एक बड़े बंगले के रूप में तैयार किया गया है। जिसका उपयोग अंबरीश शर्मा राजनीतिक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह आवास केवल जनपद पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित होता है लेकिन अंबरीश शर्मा ने गैर कानूनी रूप से इसको भी अपने नाम से आवंटित करवा लिया है। लहार वाले आवास को लेकर विधानसभा में प्रश्न भी लगा था।

अनुपस्थिति के बाद उनके पुत्र आलोक शुक्ला को मुख्य अतिथि बनाए जाने की चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए। सरकारी कार्यक्रम किसी परिवार विशेष की निजी जागीर नहीं हो सकते। यदि प्रशासन किसी मंत्री के परिजन को केवल राजनीतिक

सुधांशु द्विवेदी, प्रियंका द्विवेदी, श्रेतिमा गुप्ता और जागृति देवी ने ठगे 60 लाख रूपये

इंदौर के अनाज कारोबारी जय लक्ष्मी फूड के प्रोपराइटर राजदीप सिंह से सुधांशु द्विवेदी, प्रियंका द्विवेदी, श्रेतिमा गुप्ता और जागृति देवी ने 60 लाख रूपये की ठगी की थी। गेहूं एवं मूंग के नाम पर उक्त चारों ने अपने खातों में कुल 1,12,88,100 रूपए ट्रांसफर करवाकर 30,56,530 रूपए के गेहूं तथा 23,51,255 रुपए की मूंग को राजदीप सिंह दी गई एवं उक्त बची राशि 68 लाख 80 हजार 315 रूपए के ना तो अनाज दिया एवं ना ही रूपए वापस किये। प्रियंका द्विवेदी, सुधांशु द्विवेदी, जागृति व अन्य के खिलाफ जयलक्ष्मी फूड्स कंपनी के राजदीप श्रीवास्तव ने लसूड़िया थाना पुलिस इंदौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी प्रियंका द्विवेदी पति अमित सोनी उम्र 39 साल निवासी-252 एफ पॉकेट 01 मयूर विहार फेस-1 नई दिल्ली को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। प्रियंका दिल्ली में सूर्या ट्रेडिंग और सूर्या कंसल्टेंसी के नाम से कंपनी चलाती है। जिस पर न्यायालय में आरोपी एवं फरियादी का राजीनामा हो गया था जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी प्रियंका की जमानत स्वीकार की गई थी एवं शेष आरोपी सुधांशु द्विवेदी एवं श्रेतिमा गुप्ता की अग्रिम जमानत हुई। इन दोनों कंपनियों के खाते में भी लाखों रूपए जमा कराए गए। इसके अलावा कुछ और व्यापारियों के खाते में भी रुपया जमा कराया है और अब तक अनाज नहीं दिया है। इनके खिलाफ अपराध क्रमांक 1258/2019 धारा 420, 406, 34 भादवि के तहत मुकदमा किया गया था।

पत्नी श्रेतिमा के साथ सुधांशु द्विवेदी

प्रभाव के कारण मंच पर प्रमुखता देता है, तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता की भावना के विपरीत माना जाएगा। इससे यह संदेश जाता है कि जिले का प्रशासनिक ढांचा जनहित के बजाय राजनीतिक प्रभाव के अनुसार संचालित हो रहा है।

विधायक अंबरीश शर्मा की धौंस देकर सुधांशु द्विवेदी ने व्यापारी संदीप कुमार के हड़प लिये लगभग तीन करोड़ रूपये

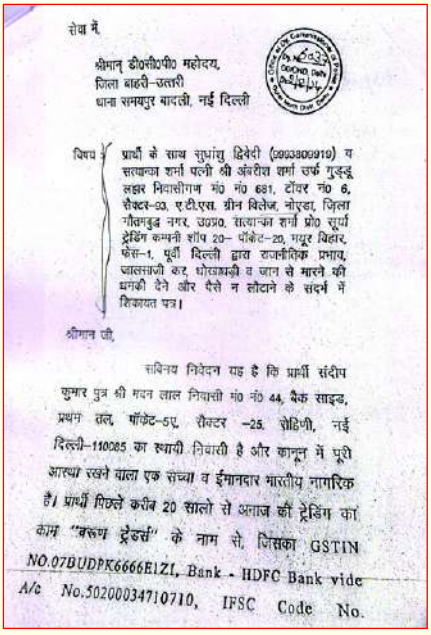

सेवा में,

श्रीमान् डीसीपी० महोदय,
जिला बाहरी-उत्तरी
थाना समयपुर बादली, नई दिल्ली

विषय- प्रार्थी के साथ सुधांशु द्विवेदी (9953809919) व सत्यवक्ता शर्मा पत्नी श्री अंबरीश शर्मा उर्फ गुड्डू लहर निवासीगण मं० नं० 681, टॉवर नं० 6, सैक्टर-93, ए.टी.एस. ग्रीन विलेज, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०. सत्यवक्ता शर्मा प्रो० सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी शॉप 20- पॉकेट-20, मयूर विहार, फेस-1, पूर्वी दिल्ली द्वारा राजनीतिक प्रभाव, जालसाजी कर, धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी देने और पैसे न लौटाने के संदर्भ में शिकायत पत्र।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी संदीप कुमार पुत्र श्री मदन लाल निवासी मं० नं० 44, बैक साइड, प्रथम तल, पॉकेट-5ए, सैक्टर -25, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 का स्थायी निवासी है और कानून में पूरी आस्था रखने वाला एक सच्चा व ईमानदार भारतीय नागरिक है। प्रार्थी पिछले करीब 20 सालो से अनाज की ट्रेडिंग का काम "वरूण ट्रेडर्स" के नाम से, जिसका GSTIN NO.07BUDPK6666E1ZI, Bank - HDFC Bank vide A/c No.50200034710710, IFSC Code No.

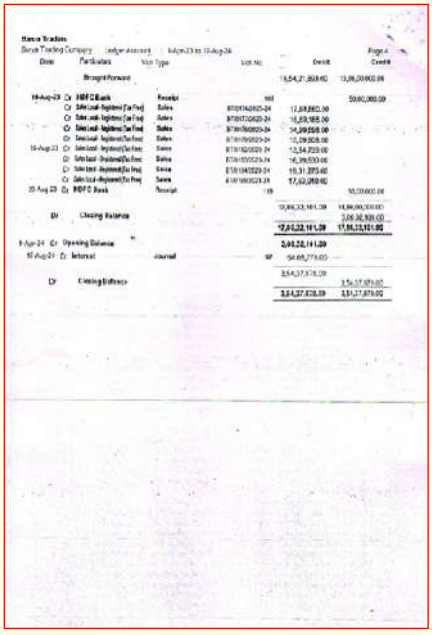

संदीप कुमार सेक्टर- 25, रोहिणी, नई दिल्ली का निवासी है। संदीप कुमार पिछले करीब 20 सालों से अनाज की ट्रेडिंग का काम वरूण ट्रेडर्स के नाम से कर रहा है। जिसका GSTIN NO.07BUDPK6666EIZI, Bank- HDFC Bank vide A/c No. 50200034710710, IFSC Code No HDFC0000330, Branch Mori Gate, Kashmere Gate, Delhi पता शॉप नंम्बर 147-148, तीसरी मंजिल, पॉकेट-2, सैक्टर-25, रोहिणी है। संदीप कुमार ने बताया कि सुधांशु द्विवेदी नाम का व्यक्ति मेरे ऑफिस रोहिणी आया और अपना परिचय दिया कि मैं सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी का मालिक हूँ, जिसका GSTIN NO. 07DSYPS6660DIZZ, Bank Kotak Mahindra, A/c No.9845167459, IFSC Code KKBK0004602, Branch Jor Bagh, New Delhi है और इस नाम से अनाज की ट्रेडिंग का काम करता है। मेरा ऑफिस मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली में है। मैं आपके साथ अनाज के व्यापार का काम करना चाहता हूँ और उसी दिन हम दोनों की आपसी सहमति से व्यापार की लेन-देन की बातें हो गयी। जिस पर मैंने अपनी कम्पनी वरूण ट्रेडर्स से सूर्या ट्रेडर्स कम्पनी को 03.01.2023 से 16.08.2023 तक चना दिया। सभी लेन-देन में करीब लगभग 21,79,88,306.00 का माल दिया, जिसमें से सुधांशु द्विवेदी ने सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी के बैंक कोटक महिन्द्रा

आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप

चंबल क्षेत्र पहले ही अपराध और अवैध गतिविधियों की छवि से लंबे समय तक संघर्ष करता रहा है। ऐसे में यदि किसी जनप्रतिनिधि पर असामाजिक तत्वों को

बैंक से आर.टी.जी.एस. (Cr.-KKBK0000958) के माध्यम से संदीप कुमार की कम्पनी वरूण ट्रेडर्स के बैंक खाते में जनवरी 2023 से लेकर दिनांक 23.08.2023 तक 18,97,20,115.00 का भुगतान किया और बकाया धनराशि 2,82,68,191.00 का भुगतान नही किया। सुधांशु द्विवेदी व उसकी कम्पनी सूर्या ट्रेडर्स ने संदीप कुमार पर अपना विश्वास जमा कर अगस्त 2023 में लगातार काफी माल उधार खरीद लिया और विश्वास करके माल ट्रकों के माध्यम से सूर्या ट्रेडिंग को भेज दिया था। जब सुधांशु द्विवेदी से अपनी बकाया धनरशि की माँग की तो सुधांशु द्विवेदी आज कल आज कल करके पेमन्ट करने के लिए टालता रहा। जब बार-बार फोन किया तो फोन पर गंदी-गंदी गालियाँ दी और कहा कि तु मुझे जानता नही है। मेरा जीजा अमरीश शर्मा विधायक है और पुलिस में मेरी अच्छी जान-पहचान है। पुलिस हमारी जेब में रहती है और बड़े-बड़े गुंडे-बदमाशों से हमारे सम्बन्ध हैं। हम तुझे जब चाहे तब जान से मरवा देंगे। यह सब देखकर सुनील कुमार और उसका परिवार सदमें में आ गया और कुछ दिन बाद संदीप कुमार सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी के पते मयूर विहार, दिल्ली गया तो देखा कि वहाँ इस नाम का कोई ऑफिस नही है। फिर संदीप कुमार उसके घर नोएडा का पता निकालकर पहुँचा तो वहाँ पर सुधांशु द्धिवेदी की पत्नी व उसकी बहन सत्यांका शर्मा मिली और जब उन्हें उपरोक्त लेन-देन के विषय में बताया तो उन्होंने भी प्रार्थी संदीप कुमार के साथ गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तू नही जानता कि मेरा पति विधायक है और कहा कि सूर्या ट्रेडर्स की मालिक तो मैं हूँ और मैंने तेरे साथ कोई लेन-देन नही किया, ना ही मैं तुझे जानती हूँ। संदीप कुमार ने कहा कि सुधांशु द्विवेदी व उसकी बहन सत्यांका शर्मा व विधायक अम्बरीश शर्मा ने जालसाजी करके धोखाधड़ी की है। संदीप कुमार ने उक्त के संबंध में डीसीपी जिला बाहरी-उत्तरी, थाना समयपुर बादली, नई दिल्ली में शिकायत की थी।

संरक्षण देने के आरोप लगते हैं, तो यह पूरे क्षेत्र की सामाजिक संरचना के लिए चिंता का विषय बन जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई ऐसे तत्व, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वे राजनीतिक संरक्षण के कारण खुले तौर पर सक्रिय हैं। यदि सत्ता

सुधांशु द्विवेदी पर एक महिला ने लगाया रेप का आरोप

ग्यालियर निवासी सलमा ने 14.07.25 को थाना लहार में आवेदन देकर सुधांशु द्विवेदी पर कई गंभीर आरोप लगाये। इसके बाद प्रथम दृष्टया लहार निवासी सुधांशू द्विवेदी एवं रवि के विरूद्ध अपराध धारा 70, 351 (3), 296, बीएनएस का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आवेदन में सलमा ने बताया कि मेरे तीन बच्चे हैं। मैं मेरे पति से 12 साल से अलग रहती हूं। मेरा करीब तीन साल पहले सुधांशु द्विवेदी नाम के आदमी से ग्वालियर में शादी में परिचय हुआ था। मैं अकेली अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उन्हें ये पता था तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। उसके बाद मेरी उनसे फोन पर बात होती थी। फिर 22 मार्च 2025 को उनका फोन आया बोले कि मैंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है। तुम लहार आ जाओ। मैं दिनांक 23.03.2025 को शाम करीब 04.00 बजे लहार बस स्टैण्ड आ गयी। बस स्टैण्ड पर सुधांशू द्विवेदी मुझे लेने आये और किसी के घर ले गये। वहां कोई और नहीं था। मुझे ठण्डा पिलाया। थोड़ी देर में मुझे मुझे नींद सी आने लगी तो सुधांशू द्विवेदी ने मेरे साथ जबरदस्ती कर गलत काम किया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मुझे थप्पड़ मारे और मुझे गंदी-गंदी गाली दीं। फिर सुधांशू द्विवेदी वहां से चला गया। थोडी देर में रवि नाम का आदमी आया जो सुधांशू द्विवेदी के साथ रहता है। वो मुझसे बोला कि जो भी हुआ है उसके बारे में किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर देंगे। ग्वालियर में भी बचेगी नही। यहां से जल्दी निकल जा। मैं धमकी से बहुत डर गयी थी। इसलिये कहीं रिपोर्ट नहीं करायी। मैंने अपनी मां ये बात बतायी।

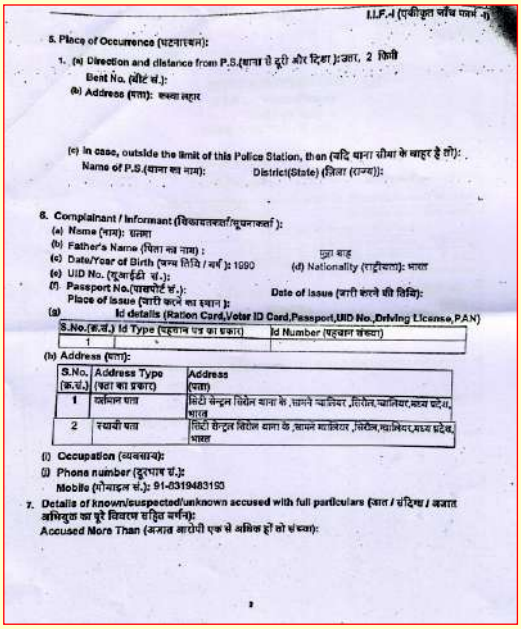

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 2 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): कस्बा लहार

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): सलमा
(b) Father's Name (पिता का नाम) : मुन्ना शाह
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सिटी सेन्ट्रल सिरोल थाना के ,सामने ग्वालियर ,सिरोल,ग्वालियर,मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सिटी सेन्ट्रल सिरोल थाना के ,सामने ग्वालियर ,सिरोल,ग्वालियर,मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):
(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-8319483190
7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

का उपयोग कानून व्यवस्था मजबूत करने के बजाय संरक्षणवाद के लिए होने लगे, तो इससे जनता का विश्वास कमजोर होता है।

मध्यप्रदेश की वर्तमान सरकार लगातार सुशासन, पारदर्शिता और विकास की बात करती रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी

मुंबई पुलिस ने साइबर फ्रॉड मामले में सुधांशु द्विवेदी को भोपाल से किया था गिरफ्तार

साइबर फ्रॉड के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने भोपाल से सुधांशु को गिरफ्तार किया था। करोड़ों रूपए के फ्रॉड के मामले में सुधांशु की गिरफ्तारी हुई थी। मामला इतना हाई प्रोफाइल थी कि जिसकी जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच ने भोपाल पुलिस को देना जरूरी नहीं समझा। सुधांशु के साथ पत्नी को भी पकड़े जाने की जानकारी भी सामने आई थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास 01 करोड़ की गाड़ी भी मिली थी। विधायक अमरीश शर्मा के रूतबे और रसूख के कारण पुलिस प्रशासन ने भी इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन बाद में पूरी सच्चाई सबके सामने आयी।

प्रशासनिक कसावट और जवाबदेही पर जोर देते दिखाई देते हैं। ऐसे में यदि किसी मंत्री को लेकर लगातार विवाद सामने आते हैं, तो सरकार की छवि प्रभावित होना स्वाभाविक है। विपक्ष को भी ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का अवसर मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार इन आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में आरोप लगना और उनका सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराने से पहले तथ्यों और जांच की प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। लेकिन जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक एक जैसे आरोप और चर्चाएं बनी रहें,

लहार बीजेपी विधायक अंबरीश शर्मा ने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खड़ा किया आपराधिक साम्राज्य

अंबरीश शर्मा की पत्नि के नाम फर्जी सूर्या ट्रेडिंग कंपनी में करोड़ों का गबन

तो सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे स्थिति स्पष्ट करें।

विधायक अंबरीश शर्मा के साले सुधांशु द्विवेदी की दबंगई

विधायक अंबरीश शर्मा के राजनीतिक प्रभाव के साथ-साथ उनके साले सुधांशु द्विवेदी की सक्रियता भी बढ़ी। अंबरीश शर्मा का पूरा समर्थन अपने साले को दिया जा रहा है। क्षेत्र में अवैध धंधों में दोनों की सामूहिक साझेदारी है। अंबरीश शर्मा के राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि के साथ उनके करीबी लोगों और रिश्तेदारों की सक्रियता भी स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बनी है। इन्हीं नामों में सुधांशु द्विवेदी का उल्लेख भी स्थानीय स्तर पर किया जाता है। चुनाव जीतने के बाद उनकी क्षेत्रीय पकड़ और

अमित सोनी पर एक करोड़ नहीं देने पर एफआईआर

पुलिस थाना कोतवाली जिला खरगोन में दिनेश जायसवाल द्वारा लक्ष्मीनगर दिल्ली निवासी विष्णुपनि उद्योग प्रा.लि. के अमित सोनी की शिकायत आवेदन पेश कर करीब 01 करोड़ रूपये से अधिक की बकाया राशि नही देने के संबंध में शिकायत की है। शिकायत के संबंध में खरगोन पुलिस ने दस्तावेज के साथ दिनांक 20.09.25 को थाना कोतवाली पर उपस्थित होने का आदेश दिया था। सूत्रों का कहना है कि अमित सोनी अंबरीश शर्मा का खास व्यक्ति है।

कार्यालय पुलिस थाना कोतवाली जिला खरगोन (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक / 1686-ए /25

दिनांक 13/09/2025

प्रति

श्री अमित सोनी दिल्ली मो. 8384061420

हाल:- Shop No.28 ,Mocher deiry complex , pocket 1 , Mayur vihar phase 1 , New Delhi , East Delhi ,Delhi , 110091

... दिनांक 22/08/25 को आवेदक दिनेश जायसवाल नि. खरगोन के द्वारा शिकायत आवेदन पेश कर करीब 1 करोड रुपये से अधिक की बकाया राशी नही देने के संबंध में शिकायत की है ... दिनांक 20.09.25 को थाना कोतवाली पर उपस्थित होवे।

मो.न.8770522106

राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ा। राजनीतिक कार्यक्रमों, सामाजिक आयोजनों और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी उपस्थिति को लेकर विपक्षी दलों ने कई बार सवाल उठाए। बीजेपी के नेताओं के साथ अक्सर देखा जाता है। मंचों को साझा किया जाता है। सुधांशु द्विवेदी भले ही क्षेत्र में नहीं रहते हों लेकिन क्षेत्र की हर गतिविधि में उनका हस्तक्षेप होता है। राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में सुधांशु द्विवेदी की उपस्थिति संदेह को और गहरा करती है। विरोधियों का आरोप रहा कि विधायक के प्रभाव का लाभ उनके करीबी लोगों तक पहुंचता है। भारतीय राजनीति में यह सामान्य प्रवृत्ति रही है कि प्रभावशाली नेताओं के परिवार और रिश्तेदार भी सामाजिक या राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। कई बार यह सक्रियता जनसेवा के रूप में देखी जाती है, जबकि यह परिवारवाद या प्रभाव विस्तार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लहार की राजनीति में भी यही स्थिति दिखाई देती है। यह कहा जा सकता है कि अंबरीश शर्मा के राजनीतिक प्रभाव के बढ़ने के साथ सुधांशु द्विवेदी की सक्रियता भी स्थानीय राजनीति में अधिक दिखाई देने लगी है। इसी दौरान सुधांशु द्विवेदी का नाम भी स्थानीय राजनीति में सामने आने लगा। विपक्षी दलों और कुछ स्थानीय लोगों का आरोप रहा कि विधायक के रिश्तेदार होने के कारण उन्हें क्षेत्र में अतिरिक्त प्रभाव प्राप्त है। बीजेपी में परिवारवाद का मुद्दा नया नहीं है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय निकायों तक, नेताओं के रिश्तेदार राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। लहार में भी अंबरीश शर्मा और सुधांशु द्विवेदी को लेकर इसी प्रकार की चर्चाएं होती रही हैं।

सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से किया करोड़ों का फ्रॉड

विधायक अंबरीश शर्मा की पत्नी के नाम पर दिल्ली में सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी खोली है। यह कंपनी एकदम फर्जी है क्योंकि इस कंपनी का जो पता दिया गया है वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन इस फर्जी कंपनी के नाम पर विधायक और उसके परिजनों ने करोड़ों का फ्रॉड किया है। अनाज का सारा लेनदेन इसी कंपनी के नाम पर होता था। अनाज की ढुलाई में जो वाहन दर्शाये जाते थे वह भी इसी कंपनी से संबंधित बताये जाते थे। इस फर्जी कंपनी के कारण कई व्यापारियों को पैसा डूब गया है।

विधायक अमरीश शर्मा के परिवारजनों का सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा

वनखण्डेश्वर मंदिर

लहार नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर विधायक अंबरीश शर्मा के पिता और परिजनों का कब्जा है। वनखण्डेश्वर मंदिर में नरेश चन्द्र शर्मा का अवैध रूप से आवास बना हुआ है। ऐसे और कई मामले हैं जहां पर गैरकानूनी रूप से कब्जे किये जा रहे हैं।

अंबरीश शर्मा की राजनीतिक रणनीतियों में उनके करीबी लोगों की भूमिका रहती है। राजनीतिक कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और संगठनात्मक गतिविधियों में सिधांशु द्विवेदी की उपस्थिति को लेकर कई चर्चाएं होती रही हैं।

विधायक अंबरीश शर्मा के बिगड़े बोल

भोपाल से संगठन प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार नसीहत दे रहे हैं कि सोच-समझकर बयानबाजी करें। लेकिन लहार के भाजपा विधायक अंबारीश शर्मा ने पिछले वर्ष विवादास्पद बयान देकर पार्टी की किरकिरी कराई थी। उन्होंने कहा- तलवार में धार लगाकर रखी है। अब लहार में महासंग्राम होगा। अंबरीश शर्मा ने कांग्रेस को कुकुरमुत्ता बताया। मैं लहार में हूं। अगर ताकत है, अगर बाप की औलाद हो, तो सामने आकर दहाड़ो। मैं कहीं यात्रा पर चला गया तो कुत्ते भौंकने लगे।

विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए साय सरकार के ढाई साल

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में विकास और जनकल्याण को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासी समुदाय और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े अनेक कदम उठाए हैं। सरकार का दावा है कि उसने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य किया है, जबकि विपक्ष इन दावों की समीक्षा और आलोचना भी करता रहा है। इसके बावजूद यह तथ्य सामने आता है कि सरकार ने अपने शुरूआती कार्यकाल में कई बड़े फैसलों के माध्यम से प्रशासनिक सक्रियता का परिचय दिया है।

किसानों के लिए प्राथमिकता

विष्णुदेव साय सरकार ने सत्ता संभालते ही किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का भरोसा दिया था। सरकार ने धान खरीदी और किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए। किसानों को कृषि कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, सिंचाई परियोजनाओं को गति देने तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना समग्र विकास संभव नहीं है। कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग और किसानों की आय बढ़ाने के

लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। सरकार का दावा है कि महिला समूहों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास

राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तथा निवेश को आकर्षित कर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में भी पहल की गई है। सरकार का कहना है कि औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए दीर्घकालिक रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आदिवासी विकास पर विशेष फोकस

विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्रों के विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। राज्य के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के प्रयास किए गए हैं। आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की मुख्यधारा से दूर रहे समुदायों को भी समान अवसर प्राप्त हों।

बुनियादी ढांचे के विकास को गति

राज्य सरकार ने सड़क, पुल, भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को गति देने का प्रयास किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के लिए मजबूत आधारभूत संरचना आवश्यक होती है। इसी दृष्टिकोण से सरकार परिवहन, उर्जा और नगरीय विकास के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर दे रही है।

कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार

सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए

हैं। राज्य सरकार का दावा है कि जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास भी किया गया है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की पहल

छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहा है। विष्णुदेव साय सरकार ने सुरक्षा उपायों के साथ-साथ विकास आधारित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि विकास और विश्वास के माध्यम से ही प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। इसी उद्देश्य से कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में प्रयास

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति पर ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भी प्रयास जारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों के उन्नयन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को राज्य के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना है।

निवेश और औद्योगिक विकास

छत्तीसगढ़ को औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है। उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां, निवेशकों के साथ संवाद और नई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के खनिज संसाधनों और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उद्योग क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकार इन्हीं संभावनाओं को वास्तविक निवेश और रोजगार में बदलने की दिशा में काम कर रही है।

विपक्ष की आलोचना भी जारी

जहां सरकार अपने कार्यों और उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है, वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कुछ वादों को पूरी तरह लागू करने में अभी समय लगेगा और कई क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सरकार के प्रदर्शन का अंतिम मूल्यांकन उसके पूरे कार्यकाल के आधार पर ही किया जाना चाहिए। फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी दलीलों के साथ जनता के बीच सक्रिय हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शुरूआती कार्यकाल में किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और विकास परियोजनाओं के माध्यम से सरकार राज्य के समग्र विकास का दावा कर रही है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं और नीतियों के वास्तविक परिणाम राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, यह देखने योग्य होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरूआत सक्रिय निर्णयों और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के साथ की है, जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन में नई दिशा देने का प्रयास दिखाई देता है।

पीएम मोदी की अपील के मायने

क्या देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है?

■ विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय-समय पर देशवासियों और आर्थिक हितधारकों से अपील करते हैं, जो केवल राजनीति नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण होती हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए वैश्विक परिदृष्य के मददेनजर कई अपीलें की हैं। जैसे सोना मत खरीदों, विदेश यात्रा मत करो, खाने के तेल का उपयोग कम करो और सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल-डीजल का कम उपयोग करो। मोदी की इन अपीलों से लग रहा है कि देश के अंदर आर्थिक हालात बदतर हो गये हैं। आज भले ही मोदी सरकार इन आरोपों से सही नही ठहरा रही हो लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नही है। हालांकि यह अवसर नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की हो। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने जब देश के अंदर अन्न की कमी थी तो उन्होंने सप्ताह में एक दिन उपवास करने की अपील की थी। 1971-73 के बीच इंदिरा गांधी ने भी संयम, सहयोग और स्वदेशी उत्पादन के संदेश को आगे बढ़ाया था। लेकिन उस समय के भारत और आज के भारत में काफी अंतर था। आज भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर है। मोदी सरकार अपनी ताकत और आर्थिक स्थिति को मजबूत बताती आ रही है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी को अपील करने की जरूरत पड़ी। यही सवाल आज हर एक देशवासी के अंदर कुरेद रहा है। आज भारत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोगों के मन सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश 1991 जैसे हालात से गुजर रहा है। क्या मोदी सरकार आर्थिक आपातकाल लगाने की तैयारी में है। यह ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं। आर्थिक चुनौतियों पर मोदी सरकार की चुप्पी या कम मुखर होने का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में पैनिक (घबराहट) को रोकना, निवेशकों का भरोसा बनाए रखना और विकसित भारत की छवि को सुरक्षित रखना है। सरकार खुले तौर पर मंदी या संकट कहने के बजाय स्थिति को वैश्विक दबाव और सुधार के अवसर के रूप में पेश कर रही है। वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, पश्चिम एशिया के युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने वैश्विक आर्थिक संकट और महंगाई को गंभीर बना दिया है। इससे भारत में भी आम आदमी का जीवन-यापन कठिन हो रहा है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है।

युद्ध तो बहाना है, हालात पहले से बेकाबू

अमेरिका-इजराइल-ईरान के मध्य चल रहे युद्ध के बीच मोदी सरकार ने देश के भीतर संकट के संकेत दे दिये हैं। देश आर्थिक संकट जूझ रहा है। भारतीय रूपया दिनोंदिन गिरता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कमी के चलते भारत पर भी असर दिखने लगा है। युद्ध के दो महीनों से अधिक समय के बाद सरकार ने युद्ध के असर को माना है। प्रधानमंत्री की अपील इसी से जुड़ी हुई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि युद्ध तो केवल बहाना है भारत के हालात तो पहले से ही खराब है। कूटनीतिक रूप से भारत की हार हुई है। आर्थिक मंदी के चलते देश में हाहाकार मचा है। भारत सरकार पहले तो यह मानने को ही तैयार नहीं थी कि देश में आर्थिक मंदी है। फिर चारों ओर से आ रहें आर्थिक आंकड़ों

युद्ध के दो महीनों से अधिक समय के बाद सरकार ने युद्ध के असर को माना है। प्रधानमंत्री की अपील इसी से जुड़ी हुई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि युद्ध तो केवल बहाना है भारत के हालात तो पहले से ही खराब है।

में लगातार गिरती बिक्री और गिरती जीडीपी ने सरकार को यह स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया कि मंदी एक वास्तविकता है। तब सरकार पर यह दवाब आया कि मंदी को रोकने के उपाय किये जायें। सरकार ने कुछ फौरी उपायों की घोषणा भी की जिसमें प्रमुख था देश के कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर देना, जिससे कॉर्पोरेट्स को 1.45 लाख करोड़ रूपये का फायदा हुआ लेकिन सरकार का यह दांव उल्टा पड़ा क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने सारी टैक्स रिबेट खुद ही हजम कर ली आगे उपभोक्ता को नहीं दी नतीजा इकोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा बड़ा उपाय सरकार ने किया कि सरकारी बैंक्स को 70,000 करोड़ रूपया अपनी बुक्स ठीक करने के लिये दे दिया। अब इसका प्रभाव तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालाँकि यह रकम भी उंट के मुँह में जीरे के समान ही है क्योंकि

बैंक्स का NPA 8 लाख करोड़ को पार कर गया है। इन दो उपायों के अलावा सरकार ने अन्य किसी उल्लेखनीय उपाय की अभी तक कोई घोषणा नहीं की हैं। असल में सरकार कि कर्तव्यविमूढ़ हो गई है जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि इस स्तिथि में करे क्या। असल में सरकार के पास राजनैतिक और चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ तो है पर कोई अर्थशास्त्री नहीं है। अर्थशास्त्र का साधारण सा नियम है कि आप पैसा या रिबेट देश के मध्यम या गरीब वर्ग को दीजिये तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेंगी क्योंकि गरीब आदमी पैसा मिलते ही बाजार में पहुंचेगा और खाने पीने या रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं खरीदेगा जब वो सामान खरीदेगा तो डिमांड पैदा होगी, डिमांड होगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो आपको इकोनॉमी बढ़ेगी और आप मंदी से बाहर निकल आएंगे।

मुद्रास्फीति और महंगाई चिंताजनक

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगातार विकास के पथ पर रही है, लेकिन मुद्रास्फीति और महंगाई की समस्या इसके लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। यह न केवल आम जनता की जीवनशैली को प्रभावित करती है, बल्कि देश के आर्थिक स्थायित्व और विकास पर भी गहरा असर डालती है। खाद्य पदार्थों, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने आम जनता की क्रय शक्ति पर दबाव डाला है। रूपया 96 रूपये प्रति डॉलर के उपर जा चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। पेट्रो पदार्थों के आयात के कारण देश की हालत खराब हो चुकी है। खासकर ईरान-अमेरिका-इजराईल युद्ध के बाद को स्थिति और खराब हुई है। वहीं मंहगाई की बात करें तो लगातार बढ़ती मंहगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। खादय पदार्थों के साथ अन्य सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत में महंगाई का सबसे गंभीर प्रभाव मध्यम और निम्न आय वर्ग पर पड़ता है। जब रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएँ- जैसे

खाद्य पदार्थों, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने आम जनता की क्रय शक्ति पर दबाव डाला है। रूपया 96 रूपये प्रति डॉलर के उपर जा चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। पेट्रो पदार्थों के आयात के कारण देश की हालत खराब हो चुकी है। खासकर ईरान-अमेरिका-इजराईल युद्ध के बाद को स्थिति और खराब हुई है।

खाद, खेती और किसानों की आशंका

कृषि क्षेत्र में भी इस अपील को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री की अपील का देश की कृषि पर ख़तरनाक असर पड़ सकता है। देश में खाद की खपत बढ़ी है, क्योंकि सिंचाई का रकबा बढ़ा है। अब ऐसे में अगर किसान को यूरिया और डीएपी नहीं मिलेगी तो वो तो कंगाल हो जाएगा। यह समय ऐसा है, जब खाद की जरूरत बढ़ने वाली है। मध्य भारत के राज्यों में तो खाद के संकट पहले से मंडरा रहे हैं। ऐसे में खाद का कम उपयोग करने की बात बाज़ार में उथल-पुथल पैदा करेगी। अगर सरकार को लग रहा है तो वो खाद की कीमत बढ़ा दे क्योंकि वैसे ही किसान को कालाबाज़ारी के चलते खाद महंगी ही मिल रही है लेकिन खाद की आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं, वरना देश के खाद्यान्न भंडार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि सरकार का कहना है कि खाद का स्टॉक पर्याप्त है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 11 मई तक देश में कुल खाद भंडार 199.65 लाख टन था, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है।

राशन, तेल, गैस, सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं, तो परिवार की खरीदारी क्षमता घट जाती है। बचत और निवेश कम हो जाता है और लोग केवल मूलभूत जरूरतों पर खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर खर्च भी प्रभावित होता है, जिससे जीवन स्तर गिरता है। महंगाई का प्रभाव केवल जनता तक सीमित नहीं है। उद्योग और व्यवसाय भी इससे प्रभावित होते हैं। उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा अस्थिर महंगाई निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है, जिससे देश में निवेश और आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है। भारत में बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। फसल उत्पादन में कमी, अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी जैसी वजहों से महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। इस स्थिति में मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की जीवनशैली सीधे प्रभावित होती है। अगर

विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मज़बूत है, उसका एक मानक यह भी है कि उस देश के केंद्रीय बैंक के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में दुनिया भर में अमेरिकी मुद्रा डॉलर, ईयू की मुद्रा यूरो और चीनी मुद्रा युआन शामिल हैं। दरअसल, इन मुद्राओं में ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। यानी भारत गल्फ से तेल ख़रीदता है तो उसका भुगतान अपनी मुद्रा रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में करना होता है। कई देश यूरो और युआन भी स्वीकार करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार आता कहाँ से है? भारत जब सामान ख़रीदता है तो डॉलर में भुगतान करता है और बेचता है तो डॉलर ही लेता है। यानी आप बेचते ज्यादा हैं तो डॉलर ज्यादा आएंगे और खरीदते ज्यादा हैं तो डॉलर ज्यादा खर्च करने होंगे। ऐसे में कोई देश निर्यात ज्यादा करता है तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार भरा रहेगा और आयात ज्यादा करता है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव ज्यादा रहेगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का व्यापार घाटा 333.2 अरब डॉलर का था। यानी भारत ने निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा किया। भारत अपनी जरूरत का 90 फीसदी तेल आयात करता है, ऐसे में सबसे ज्यादा डॉलर इसी पर खर्च होता है। आंकड़ों के अनुसार, निर्यात और आयात के बीच का अंतर जनवरी महीने में बढ़कर 34.68 अरब डालर हो गया था जबकि एक महीने पहले यह 25.05 अरब डॉलर था। जनवरी में आयात सालाना आधार पर 19.2 प्रतिशत बढ़कर 71.24 अरब डालर हो गया जबकि निर्यात केवल 0.6 प्रतिशत बढ़कर 36.56 अरब डालर रहा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक अस्थिरता भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर गंभीर दबाव डाल रही हैं। सोने के आयात और विदेशी यात्राओं पर खर्च कम करने से भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 प्रतिशत घटकर 690 अरब डॉलर रह गया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक रूपये की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए डॉलर बेच रहा है।

मुद्रास्फीति और महंगाई अनियंत्रित रह जाती है, तो यह सामाजिक असंतोष और आर्थिक अस्थिरता का कारण भी बन सकती है। मुद्रास्फीति और महंगाई भारत के लिए केवल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चिंता का विषय भी है। इसका प्रभाव आम जनता से लेकर उद्योग, निवेश और सरकारी नीतियों तक महसूस किया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार और RBI मिलकर सतत नीति निर्माण और नियंत्रण के माध्यम से कीमतों को स्थिर रखें, ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता दोनों सुनिश्चित हो सकें।

विनिमय दर और विदेशी निवेश

रूपये की विनिमय दर और विदेशी निवेश में अस्थिरता ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाया है। इससे

स्पष्ट होता है कि देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से संकटग्रस्त है, चुनौतियों से जूझ रही है और सुधार की दिशा में तेजी की आवश्यकता है। निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। जिसका सीधा असर हमारी करेंसी पर पड़ रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र अभी भी कमजोर हैं। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसान कई परेशानियों से जूझ रहा है। खाद, बीज जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी उत्पादन पर प्रभाव डाल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की गतिविधियाँ हैं। देश की कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है और कृषि पर निर्भर है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र की स्थिति सीधे राष्ट्रीय विकास और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करती है। हालांकि, वर्तमान में इन क्षेत्रों में कई गंभीर समस्याएँ सामने आ रही हैं, जो चिंताजनक हैं। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और स्थानीय सेवाओं पर आधारित है। लेकिन रोजगार की कमी, कम मजदूरी, गरीबी और सीमित आधारभूत सुविधाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं। छोटे किसान और मजदूर अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की अनिश्चितताओं और ऋण संकट से जूझते हैं। इसके कारण ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार धीमा है।

फसल पर निर्भरता और मौसम की अनिश्चितता: भारत में कृषि अभी भी अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। असमय बारिश या सूखा फसल की पैदावार पर बुरा असर डालता है।

कृषि लागत में वृद्धि: बीज, उर्वरक, कीटनाशक और ईंधन की बढ़ती कीमतें किसानों की आय को प्रभावित करती हैं।

सड़कों, भंडारण और बाजार तक पहुँच की कमी: उपज का सही मूल्य न मिलने और खराब बुनियादी ढांचे के कारण किसान लाभ कम पाते हैं।

ऋण और कर्ज का बोझ: छोटे और सीमांत किसान अक्सर कर्ज के जाल में

तेल की आपूर्ति पर असर

अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, मोदी ईरान युद्ध से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर अधिक यथार्थवादी तरीके से बात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नागरिकों को ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका बोझ अब तक सरकार और सरकारी तेल कंपनियां उठा रही थीं। अब तक इसका दर्द केवल तेल कंपनियां और सरकार झेल रही थीं। अब उपभोक्ताओं को भी इसमें शामिल होने का समय आ गया है। मध्य-पूर्व संघर्ष के कारण भारत रसोई गैस की कमी और तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। यह संकट ऐसे देश के लिए बड़ी चुनौती है, जिसने पिछले साल 174 अरब डॉलर का तेल और गैस आयात किया था। भारत के प्राकृतिक गैस आयात का दो-तिहाई और कच्चे तेल के आयात का आधा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सउदी अरब की अरामको ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो पेट्रोल और विमान ईंधन का भंडार खतरनाक रूप से निचले स्तर तक पहुंच सकता है। जमीन पर मौजूद ईंधन भंडार तेजी से घट रहे हैं। पेट्रोल और जेट ईंधन जैसे रिफाइंड फ्यूल में सबसे तेज गिरावट देखी जा रही है। ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद होने के बाद से दुनिया अब तक कुल एक अरब बैरल तेल आपूर्ति खो चुकी है। इसके अलावा, होर्मुज जितने सप्ताह बंद रहेगा, हर सप्ताह लगभग 10 करोड़ बैरल अतिरिक्त आपूर्ति का नुकसान होगा।

फंस जाते हैं, जिससे आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएँ बढ़ रही हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

कृषि संकट और ग्रामीण गरीबी का प्रभाव न केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। रोजगार और आय की कमी ग्रामीण उपभोग और निवेश को कम करती है, जिससे उद्योग और सेवा क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, असंतुलित विकास ग्रामीण-शहरी अंतर को बढ़ाता है और सामाजिक असंतोष को जन्म देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और

सोने से कैसा संकट?

भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। भारतीय संस्कृति में सोने का विशेष महत्व है और इसे निवेश के एक सुरक्षित जरिए के रूप में भी देखा जाता है। यह कीमती धातु भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का भी अहम हिस्सा है और मार्च के अंत तक देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 17 प्रतिशत सोने के रूप में था। विश्लेषकों का कहना है कि रूपये का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि मध्य-पूर्व का संघर्ष किस दिशा में जाता है। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है क्या उसे लोग मान लेंगे या सरकार कुछ और कदम उठाएगी? जाहिर है कि इसे लोग मान नहीं लेंगे। ऐसे में सरकार के पास कुछ और विकल्प हैं। जैसे सरकार कुछ हफ्तों में तेल की कीमत बढ़ाएगी। सोने पर टैरिफ दो साल पहले 15 प्रतिशत हुआ करता, इसे बाद में छः प्रतिशत कर दिया गया था। अब इसे फिर से 10 या 15 प्रतिशत कर सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष का भारत का मर्चेंडाइज आयात बिल 775 अरब डॉलर का था, इसमें सबसे अधिक 175 अरब डॉलर कच्चे तेल का बिल था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का 116 अरब डॉलर का था। तीसरे नंबर पर 74 अरब डॉलर का गोल्ड था। इन तीनों के आयात का विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव सबसे ज्यादा होता है। क्रूड गोल्ड में सरकार टैक्स बढ़ाकर खपत कम करना चाह रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सरकार के पास अभी कुछ करने के लिए विकल्प नहीं है।

सोना कारोबार और मध्यम वर्ग की चिंता

इस अपील से सबसे अधिक बेचैनी उन सेक्टरों में दिख रही है जिनकी रोजी-रोटी सीधे उपभोग पर निर्भर है। ऐसी कोई भी अपील करने से पहले एक बार और सोचना चाहिए। सोना न खरीदने वाली अपील से बहुत नुकसान होगा। इसका सीधा असर देश के अंदर सोना व्यापार में काम कर रहे 80 लाख लोगों पर पड़ेगा। मिडिल क्लास पर इस अपील का सबसे बुरा असर पड़ने वाला है। हमारे यहां किसी भी समस्या में सोना ही तुरंत पैसे उपलब्ध कराने वाली वस्तु है। इसलिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी सोना खरीदकर कर रखना चाहता है। अब अगर ऐसे में साल भर सोना न खरीदने की अपील मान ली जाए तो न जाने कितनी शादियां नहीं होंगी, इस पेशे से जुड़े कितने लोग बेघर हो जाएंगे। सोना सिर्फ एक लग्जरी वस्तु नहीं बल्कि बचत, शादी और संकट के समय नकदी जुटाने का जरिया भी है। ऐसे में सोना न खरीदने की अपील का असर सिर्फ कारोबार पर नहीं बल्कि सामाजिक और घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

कृषि क्षेत्र की समस्याएँ केवल किसानों या ग्रामीणों की चिंता नहीं हैं; यह राष्ट्रीय विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती हैं। सरकार, ग्रामीण समुदाय और निजी क्षेत्र को मिलकर योजनाओं और सुधारों के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाना आवश्यक है। केवल तभी भारत का समग्र आर्थिक विकास संतुलित और टिकाउ बन सकता है।

पेट्रोल बचाने, सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर उठ रहे हैं ये सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई की अपील के बाद देश में राजनीतिक गलियारे

से लेकर कारोबारियों, किसान संगठनों, अर्थशास्त्रियों और सोशल मीडिया तक में बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, एक साल तक सोना न खरीदने, घर से काम करने और किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50 फीसदी तक कम करने की अपील की है। अगर संकट लंबा चला तो सरकार को आगे चलकर पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाने, सोने के आयात पर नियंत्रण और कुछ चीजों पर राशनिंग जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक है और घरेलू मांग पूरी की जा रही है। सरकार इसे मध्य-पूर्व में संकट के बीच सामूहिक जिम्मेदारी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में कदम बता रही है। लेकिन आलोचक इसे आर्थिक दबाव के संकेत और आम लोगों पर बोझ डालने की कोशिश मान रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा कि तेल कंपनियां रोज करीब 1,000 करोड़ रूपये का नुकसान झेल रही हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा बोझ देश के नागरिकों पर न पड़े। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी की अपील की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं का सवाल है कि अगर मध्य-पूर्व संकट फरवरी से जारी था तो सरकार चुनाव खत्म होने तक का इंतजार क्यों कर रही थी? दूसरी ओर कारोबारी संगठनों ने रोजगार और मांग घटने की आशंका जताई है। किसान संगठनों ने खाद के इस्तेमाल में कमी की अपील पर चिंता जताई है। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार पहले स्थिति काबू में है कह रही थी, तो अब अचानक लोगों से ये मत करिये, वो मत खरीदें जैसी अपीलें क्यों की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि अगर ईंधन बचत इतनी जरूरी थी तो चुनाव प्रचार के दौरान हज़ारों चार्टर हवाई यात्राएं क्यों हुईं। उन्होंने कहा कि ऐसी अपीलों से बाज़ार में डर, घबराहट और निराशा फैल सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में
देश में प्रथम
1 NUMBER ONE PMAYU
98.04%
ग्राउंडिंग के साथ
देश में प्रथम
10 लाख+
आवास स्वीकृत
9 लाख+
आवास पूर्ण एवं
हितग्राहियों को
वितरित
पक्का घर बन रहा है
सशक्त और सुरक्षित जीवन का आधार
अपने सपनों का घर पाने के लिए आज ही ऑनलाइन आवेदन करें।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.pmay-urban.gov.in
स्कैन QR कोड
नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश
@pmayurbanmp

मध्यप्रदेश में पर्यटन का
नया अध्याय
पीएमश्री
हेली पर्यटन सेवा
तेज, सुरक्षित और यादगार
यात्रा का अनूठा अनुभव
आध्यात्मिक सर्किट
इंदौर - उज्जैन - ओंकारेश्वर - इंदौर ₹30,000
इंदौर - उज्जैन - इंदौर ₹14,500
इंदौर - ओंकारेश्वर - इंदौर ₹18,000
हेरिटेज सर्किट
भोपाल से चंदेरी ₹5,500
चंदेरी से ओरछा ₹2,750
भोपाल से ओरछा ₹6,500
जॉय राइड ₹3,500
भोपाल - ओरछा - भोपाल (विशेष पैकेज) ₹14,500
वाइल्डलाइफ एवं आस्था सर्किट
जबलपुर - मैहर ₹5,000
जबलपुर - बांधवगढ़ ₹6,500
जबलपुर - चित्रकूट ₹7,500
जबलपुर - कान्हा ₹6,000
मैहर - चित्रकूट ₹5,000
बांधवगढ़ - कान्हा ₹7,000
भोपाल
झीलों की नगरी, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल आधुनिक शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र
ओरछा
यहां भगवान राम स्वयं इस नगर के राजा के रूप में विराजे हैं
चंदेरी
प्राचीन किलों और हथकरघा चंदेरी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध
जबलपुर
भेड़ाघाट की संगमरमर की घाटी, धुआंधार जलप्रपात और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय अनुभव
मैहर
चित्रकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा देवी मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र
चित्रकूट
भगवान श्रीराम के वनवास से जुड़ा, आध्यात्मिक महत्व का अद्भुत स्थल
बांधवगढ़ नेशनल पार्क
सबसे अधिक संख्या में बाघों की उपस्थिति। प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन का अद्वितीय स्थल
कान्हा नेशनल पार्क
सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिज़र्व समृद्ध वन्यजीव और जैवविविधता का गढ़
इंदौर
मध्यप्रदेश की व्यापारिक राजधानी होने के साथ-साथ स्वच्छता का सिरमौर इंदौर अपने राजवाड़ा सराफा और आधुनिक जीवन के लिए प्रसिद्ध है
उज्जैन
भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और सिंहस्थ कुंभ जैसे विशाल आध्यात्मिक आयोजन के लिए विश्वविख्यात
ओंकारेश्वर
ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव
एक संपूर्ण यात्रा पैकेज
• गंतव्य स्थल पर ठहरने की व्यवस्था से लेकर भोजन, स्थानीय टैक्सी तक हर सुविधा का पैकेज
• मंदिर दर्शन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था, पर्यटन अनुभव को और खास बनाने के लिए गाइड
• हेलीपैड तक पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा
बुकिंग | www.flyola.in
air.irctc.co.in/flyola
www.transbharat.in

बंगाल विजय: क्या, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिरता सहित अवैध घुसपैठ का होगा स्थायी समाधान?

नीलेश वर्मा

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत की पूर्वी सीमाओं से जुड़े उन गंभीर प्रश्नों पर निर्णायक कार्रवाई का ऐतिहासिक अवसर बनकर सामने आया है, जिनसे देश दशकों से जूझ रहा है। बांग्लादेश सीमा के रास्ते होने वाली अवैध घुसपैठ, तस्करी, फर्जी दस्तावेज़ों के नेटवर्क और बदलते जनसंख्या संतुलन ने पूर्वोत्तर भारत से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक गहरी चिंता पैदा की है। आज केंद्र और पूर्वी भारत में राष्ट्रवादी सोच को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है, तब देश की अपेक्षा है कि सीमाओं की सुरक्षा, सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कठोर एवं ऐतिहासिक कदम उठाए जाएँ। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में भी उसके प्रभाव या सहयोगी दलों की सरकारें मौजूद हैं, तो यह प्रश्न अधिक प्रासंगिक हो गया है कि क्या अब इस चुनौती पर निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है?

हाल के राजनीतिक परिवर्तनों और बंगाल में भाजपा की बढ़ती राजनीतिक शक्तिको देश की जनता एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत-बांग्लादेश सीमा का सबसे संवेदनशील द्वार माना जाता है। यदि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय मजबूत होता है, तो सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ पर रोक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अधिक प्रभावी रणनीति लागू की जा सकती है। लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा विश्व की सबसे जटिल सीमाओं में से एक पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से गुजरने वाली यह सीमा अनेक स्थानों पर नदियों, जंगलों और घनी आबादी से होकर निकलती है। यही कारण है कि दशकों से यह क्षेत्र अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों के लिए चुनौती बना हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने समय-समय पर जनसंख्या परिवर्तन, संसाधनों पर

बढ़ते दबाव और स्थानीय पहचान पर प्रभाव को लेकर चिंता जताई है।

इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील पहलू पूर्वोत्तर भारत की सामरिक स्थिति है। भारत का संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र लगभग 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा है, जिसे सामान्यतः चिकन नेक कहा जाता है और यह मुख्य भारत से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पूर्वोत्तर की स्थिरता और सुरक्षा प्रभावित होती है, तो उसका प्रभाव केवल सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता पर भी पड़ेगा।

असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में अवैध घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र रहा है। स्थानीय समुदायों में यह आशंका समय-समय पर सामने आती रही है कि अनियंत्रित प्रवास उनकी सांस्कृतिक पहचान, भूमि, रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ा सकता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) जैसे विषय देश की राजनीति के केंद्र रहे हैं। इन अधिनियमों के द्वारा वास्तविक नागरिकों और अवैध प्रवासियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सकेगा।

वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास वह राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय दिखाई देता है, जिसकी मांग लंबे समय से की जाती रही है। केंद्र सरकार, सीमा सुरक्षा बल (BSF), राज्य प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सीमा प्रबंधन को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में अब तक फेंसिंग अधूरी है, वहाँ कार्य में तेजी लाई जा सकती है। ड्रोन निगरानी, स्मार्ट फेसिंग, थर्मल कैमरे, सेंसर आधारित तकनीक और आधुनिक खुफिया तंत्र जैसी व्यवस्थाएँ सीमा सुरक्षा को नई मजबूती दे सकती हैं। इसके साथ ही जनगणना, मतदाता सूची सत्यापन और दस्तावेजों की पारदर्शी जाँच भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। प्रशासन निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ कार्य करेगा तो वर्षों से चले आ रहे अनेक विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे।

आज भारत उस दौर से गुजर रहा है, जहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रशासनिक नियंत्रण और तकनीकी संसाधन तीनों एक साथ उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़ती राजनीतिक शक्ति और पूर्वोत्तर राज्यों में अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ इस अवसर को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती हैं। अब देश की निगाह इस बात पर टिकी है कि यह अवसर केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित रहेगा या वास्तव में घुसपैठ पर नियंत्रण, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जाएंगे।

पीएम मोदी ने दिए संकट के संकेत

रघु ठाकुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों में दो बार सार्वजनिक रूप से देश के लोगों से अपील की और सावधान भी किया है। दस तारीख को उन्होंने अपने मन की बात में विस्तार से कहा कि लोग गैस, डीजल, पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम जरूरत के मुताबिक करें। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, फिजूलखर्ची दिखावा न करें ताकि उपयोग की मात्रा कम हो। उन्होंने यह भी कहा कि सोना न खरीदें, क्योंकि सोने के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़े हैं। 4 मई 2026 को उन्होंने अपने इस अपीलनुमा बयान को पुनः दोहराया तथा कहा कि कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दबाव का सबसे बड़ा संकट है। उन्होंने तो विदेश यात्रा में नीदरलैंड तक में जाकर इन बातों को भिन्न शब्दों में दोहराया, हालांकि

> एक तो प्रधानमंत्री के सावधान करने के बाद देश में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर अफरा तफरी न मच जाये, लंबी-लंबी लाइनें न लग जाएं। दूसरे रूपये का अपमूल्यन होकर वह 01 डालर 95.28 रूपये पर पहुंच गया है। यह ऐतिहासिक गिरावट है। स्वाभाविक है कि रूपये का अपमूल्यन का फर्क विदेशी मुद्रा पर पड़ता है, क्योंकि तेल, गैस आदि का व्यापार डॉलर में होता है और उसकी तुलना में हमें अरबों रूपये रोज का भारतीय मुद्रा में घाटा होता है।

अधिकारियों ने भी तथ्य रखते हुए कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी देश के पास 60 दिनों का तेल व गैस का भण्डार है तथा यह भी कहा कि फिर भी कम खर्च करें ताकि 1619 करोड़ रोज का अतिरिक्त खर्च कम हो सके। इस कथन के दो पहलू हैं, एक तो प्रधानमंत्री के सावधान करने के बाद देश में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर अफरा तफरी न मच जाये, लंबी-लंबी लाइनें न लग जाएं। दूसरे रूपये का अपमूल्यन होकर वह 01 डालर 95.28 रूपये पर पहुंच गया है। यह ऐतिहासिक गिरावट है। स्वाभाविक है कि रूपये का अपमूल्यन का फर्क विदेशी मुद्रा पर पड़ता है, क्योंकि तेल, गैस आदि का व्यापार डॉलर में होता है और उसकी तुलना में हमें अरबों रूपये रोज का भारतीय मुद्रा में घाटा होता है।

पहले तो मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूं,

उन्होंने इस संकट की सूचना समय रहते दे दी। क्योंकि कोरोना संकट के समय उनके विलंबित सूचना देने के कारण लाखों या करोड़ों लोग असुविधा, पलायन और बड़ी संख्या में बीमारी व मौत के शिकार हुए थे इसलिये उनकी इस पूर्व सूचना का मैं उनकी समझदारी पूर्ण सुधार मानता हूँ। यह सुविदित है कि युद्ध का संकट भारी है और इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अगर इस सरकार के अलावा कोई और सरकार होती तो भी वह इस युद्ध के संकट के लिये कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिये मैं गैस, तेल आदि के दामों के बढ़ने या कठिनाई के लिये अकेले सरकार को जिम्मेवार नहीं मानता। परंतु एक बात अवश्य है कि जो अपील या लाचारी प्रधानमंत्री को अब मई 2026 में नजर आ रही है, क्या इसके मूल कारणों के बारे में उन्होंने पहले विचार किया है? हमारा देश गैस के संकट से भले ही इस प्रकार परेशान पूर्व में न रहा हो परंतु प्रदूषण से रहा है। प्रतिवर्ष कई लाख मौतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण के कारण होती हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की ओर से लगभग 1998 से धरना, प्रदर्शन, पत्रकार वार्ता और भारत सरकार को ज्ञापन देकर, यह मांग की जाती रही है कि देश में प्रदूषण का बड़ा कारण कारें हैं। अकेले दिल्ली शहर में पंजीकृत और अपंजीकृत कारों की संख्या 80 लाख से 1 करोड़ है, औसतन 5-10 लाख कारें प्रतिदिन दिल्ली के समीप बाहर के राज्यों से दिल्ली में आती रहती हैं। क्या इतनी कारों की उपयोगिता है? यह प्रश्न विचार योग्य है। हमने निरंतर एक सुझाव दिया है कि श्एक घर-एक कार्य हो और अगर यह सुझाव सरकार ने माना होता तो आज देश की कितनी विदेशी मुद्रा बचती, देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की कितनी बचत हुई होती, यह सोचा जाना चाहिए। अगर सरकार ने यह कानून बनाया होता तो देश में लगभग 4 करोड़ कारें

युद्ध का संकट भारी है और इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अगर इस सरकार के अलावा कोई और सरकार होती तो भी वह इस युद्ध के संकट के लिये कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिये मैं गैस, तेल आदि के दामों के बढ़ने या कठिनाई के लिये अकेले सरकार को जिम्मेवार नहीं मानता।

सड़कों से हटी होती। याने 40 करोड़ लीटर डीजल, पेट्रोल जिसका आज की दर पर मूल्य लगभग 4000 करोड़ रुपया होगा जो कि प्रतिदिन का बचता। याने एक साल में लगभग 15 लाख करोड़ रूपया सरकार, देश और जनता का बचेगा। प्रदूषण 60 प्रतिशत कम हो जायेगा, सड़कों पर जाम कम हो जायेगा और खेती की जमीन का अधिग्रहण कर नये नये फोरलेन, आठ लेन सड़कों व फ्लाई ओवरों की आवश्यकता उतनी नहीं होगी। परंतु यह काम प्रधानमंत्री जी को आसान नहीं है, क्योंकि कार बनाने वाली कंपनियां अकेले दीपावली के दिन ही 1 लाख से अधिक कारें दिल्ली राजधानी में बेचकर लगभग 10 हजार करोड़ का मुनाफा में कमा लेती हैं और जाहिर है कि इस मुनाफे का एक हिस्सा सत्ता, पार्टी और सत्ता के नजदीक के सत्ताकांक्षी दलों में बंटता है। इस सरकार और राजनीति से ऐसे राष्ट्रहित की अपेक्षा करना भूत से पूत मांगने जैसा है। हालांकि इस युद्ध के संकट को समझकर आज की सरकार यह कदम उठाये तो वह श्रेष्ठकर होगा।

परंतु प्रधानमंत्री का आचरण तो उनकी अपनी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री छोड़ो, विधायक, सांसद छोड़ो, साधारण कार्यकर्ता को भी नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के निरंतर झूठ के प्रयोग से वे अपनी नैतिक शक्ति और विश्वसनीयता खो चुके हैं। 11 मई को मप्र में उनकी पार्टी के उज्जैन के कार्यकर्ता जिन्हें शायद मुख्यमंत्री और संघ की कृपा से मप्र पाठयपुस्तक निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, अपने पद का प्रभार लेने उज्जैन से चलकर भोपाल आये थे। उनके काफिले में 800 से अधिक गाड़ियां थीं, याने एक छोटे से पद ग्रहण करने में लगभग 40 लाख रूपये का डीजल पेट्रोल जल गया। इस आक्रमणकारी पद ग्रहण में कितना टोल टैक्स का नुकसान हुआ, कितना जाम लगा, लोगों को कितनी परेशानी हुई, वह तो चर्चा में ही नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी मंत्री विधायकों के कार के काफ्लि, पायलट गाड़ियों के सायरन के साथ-साथ आम जनता को भयभीत करते हुए सड़कें रोंद रहे थे। मुझे एक अधिकारी ने बताया कि एक मुख्यमंत्री तो प्रत्येक दिन रात को हैलीकाप्टर से घर जाकर सुबह राजधानी में आ जाते हैं। अभी तो भाजपा और सरकार बंगाल के चुनाव को शाम दाम दंड भेद की जीत के जश्न मनाने में लगी है।

प्रधानमंत्री का आचरण तो उनकी अपनी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री छोड़ो, विधायक, सांसद छोड़ो, साधारण कार्यकर्ता को भी नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के निरंतर झूठ के प्रयोग से वे अपनी नैतिक शक्तिऔर विश्वसनीयता खो चुके हैं। 11 मई को मप्र में उनकी पार्टी के उज्जैन के कार्यकर्ता जिन्हें शायद मुख्यमंत्री और संघ की कृपा से मप्र पाठयपुस्तक निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, अपने पद का प्रभार लेने उज्जैन से चलकर भोपाल आये थे। उनके काफिले में 800 से अधिक गाड़ियां थीं, याने एक छोटे से पद ग्रहण करने में लगभग 40 लाख रूपये का डीजल पेट्रोल जल गया।

हालांकि प्रधानमंत्री का आंकलन सही है कि युद्ध के समाप्त होने की संभावनायें जल्दी नजर नहीं आती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि युद्ध के विराम की वार्ता वेंटिलेटर पर है और एक बार वेंटिलेटर पर जाने के बाद मरीज की सांस तभी तक चलती है जब तक वेंटिलेटर पर मरीज रहता है। परंतु कई दिनों के बाद ट्रम्प का यह पहला बयान आया है जो सच के करीब व गंभीर है। दरअसल अमेरिका ईरान से

अमेरिका के लिये ईरान से युद्ध गले की हड्डी बन चुका है। वह इसे न निगल पा रहा है और न उगल पा रहा है। अब अमेरिका के पास जो दूसरी योजना है, वह ईरान को हथियारों की शक्ति से निरंतर कमजोर करते रहना तथा समर्पण और परमाणु ईधन सौंपने को लाचार करना है।

इसके लिये तैयार नहीं है। अमेरिका की इस कमजोरी को अब ईरान भी समझ रहा है क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो ईरान भी समाप्त होगा, पर साथ में सटे हुए देश जो अमेरिका समर्थक या गुट में हैं वे भी अगर समाप्त नहीं तो बड़ी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। अगर प्रतिकार में ईरान परमाणु शक्ति का प्रयोग यदि वह कर सका तो फिर अमेरिका का बच पाना भी संभव नहीं है।

परास्त नहीं हुआ है बल्कि अपनी रणनीति में असफल होने के कारण फंस गया है।

जहाँ तक मेरी जानकारी में है और सीपरी के आंकड़ों के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि अमेरिका के पास आज भी ईरान व दुनिया को मिटाने की ताकत है। एक छोटा सा परमाणु बम 20 लाख लोगों की जान ले सकता है, परंतु इसका प्रयोग करना अमेरिका के लिये लगभग असंभव कार्य है। ईरान, अमेरिका और इजराइल युति का जो एक बड़ा लक्ष्य था कि ईरान के प्रभावकारी नेतृत्व को खत्म करने के बाद हताश ईरान को समर्पण के लिये लाचार किया जाये तथा जो 4600 किलो संवर्धित यूरेनियम याने परमाणु की शक्ति ईरान ने तैयार कर ली है उसे छीन लिया जाये। ईरान कुल मिलाकर अमेरिका के लिये ईरान से युद्ध गले की हडडी बन चुका है। वह इसे न निगल पा रहा है और न उगल पा रहा है। अब अमेरिका के पास जो दूसरी योजना है, वह ईरान को हथियारों की शक्ति से निरंतर कमजोर करते रहना तथा समर्पण और परमाणु ईधन सौंपने को लाचार करना है। ईरान भी अपनी इस रणनीतिक पक्ष की

ताकत को समझ गया है। इसलिये वह भी लगातार उसी भाषा में उत्तर दे रहा है, जिसमें ट्रम्प बोल रहे हैं। इसलिये अमेरिका के पास हॉर्मूज को घेरना, ईरान के तेल की निकासी को रोकना, दुनिया के दूसरे तेल जहाजों को रोक कर ईरान पर दबाव डालकर उन देशों को अपने साथ लेना या उन्हें अमेरिका के समर्थन के लिये बाध्य करना, बस यही रास्ता बचा है। ईरान के पास जो तेल के भण्डार है उसमें से वह औसतन 03 लाख टन रोज तेल निकालता है और जब ईरान का तेल आना बंद होगा या तो यह भंडार स्वतरूही नष्ट हो जायेंगे क्योंकि इनमें पानी भरेगा और ईरान आर्थिक रूप से टूटेगा। अमेरिका ने अपने युद्ध के खर्च की पूर्ति जो लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर है तेल की कीमतों को बढ़ाकर वापिस लेना शुरू किया है। ईरान ने भी होर्मूज से निकलने वाले तेल के जहाजों पर भारी भरकम टैक्स लगाकर अपने खर्च की वसूली का प्रयास किया था परंतु होर्मूज नहर भी अमेरिका की घेराबंदी से वह प्रयास बहुत प्रभावी नजर नहीं आता। अतः यह तय है कि युद्ध लंबा चलेगा और वह कई माह ले सकता है।

दुनिया में सादगी का प्रतीक महात्मा गांधी से बड़ा कोई नहीं है जिसने जीवन भर सादगी अपनाई, सादगी का पाठ पढ़ाया और संचय के विपरीत श्रम की सिफारिश की। आज अगर लाचारी से सही आप सादगी और सोने की खरीद को रोकने की अपील कर रहे हैं अगर इसमें राष्ट्रपिता को भी उद्धृत करते तो देश में एक नैतिक वातावरण बनता।

अमेरिका समर्थक शाह दहलवी को मानसिक दबाव बनाकर ईरान की सत्ता सौंपने के खेल में अमेरिका सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आज भी ईरान में ज्यादा समर्थक, ताकत और सैन्य शक्ति धर्मगुरू की परंपरा के खामनई के पास है, ईरान का बहुमत उनके साथ है। इसलिये अमेरिका की रणनीति अब जीतने की नहीं है बल्कि हाथ मरोड़ते रहने के द्वारा जीतने की है। यह लंबा युद्ध कब क्या शक्ल लेना, क्या विश्वयुद्ध में बदलेगा, क्या मानवता को नष्ट करेगा या कुछ और हल निकलेगा कहना कठिन है। नरेन्द्र मोदी को मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी जुबान से महात्मा गांधी का नाम नहीं निकलता यह उनका बौनापन व कुंठा है। दुनिया में सादगी का प्रतीक महात्मा गांधी से बड़ा कोई नहीं है जिसने जीवन भर सादगी अपनाई, सादगी का पाठ पढ़ाया और संचय के विपरीत श्रम की सिफारिश की। आज अगर लाचारी से सही आप सादगी और सोने की खरीद को रोकने की अपील कर रहे हैं अगर इसमें राष्ट्रपिता को भी उद्धृत करते तो देश में एक नैतिक वातावरण बनता।

कम खर्च में एक साथ चुनाव

प्रमोद भार्गव

एक साथ चुनाव कराने को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्ष में सोने में सुहागा कहावत चरितार्थ होने का तथ्य निकलकर आया है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दावा किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से सात लाख करोड़ रूपए की बचत होगी। इस उपाय से देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बचे धन का उपयोग बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, गरीब कल्याण योजनाएं और अन्य सेवाओं में किया जा सकेगा। याद रहे 41 सदस्यीय यह समिति एक साथ चुनाव से तमाम पहलुओं के साथ दो प्रस्तावित 129वां संविधान संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयकों के प्रारूप पर काम कर रही है। चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इन चुनाव सुधारों से देश को लाभ होना चाहिए। एक साथ चुनाव की दिशा तय करने के लिए सरकार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने मार्च 2024 में अपनी

लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से सात लाख करोड़ रूपए की बचत होगी। इस उपाय से देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बचे धन का उपयोग बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, गरीब कल्याण योजनाएं और अन्य सेवाओं में किया जा सकेगा।

विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार करते हुए चुनाव से संबंधित संशोधन विधेयक को मंजूरी भी दे दी दे थी। इसके प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी संसदीय समिति कर रही है। 2029 में एक देश, एक चुनाव, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ निकाय व पंचायत चुनाव भी एक साथ कराने की दिशा में केंद्र सरकार एक-एक कदम आगे बढ़ रही है। और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे हैं, लेकिन 1968 और 1969 में समय के पहले ही कुछ राज्य सरकारें भंग कर दिए जाने से यह परंपरा टूट गई। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में करीब 18 संशोधन करने होंगे। इनमें से कुछ बदलावों के लिए राज्यों की भी अनुमति जरूरी होगी। यदि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी साथ-साथ होते हैं तो फिर मतदाता सूची तैयार निर्वाचन हालांकि 2029 तक इस कानून का लागू होना फिलहाल असंभव लग रहा है।

चूंकि संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग इकाइयां हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में समानांतर किंतु भिन्न-भिन्न अनुच्छेद हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर होने चाहिए। लोकसभा या विधानसभा जिस दिन से गठित होती है, उसी दिन से पांच साल के कार्यकाल की

गृहमंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव का प्रबंध कर दिया जाएगा। साफ है, सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को क्रियान्वित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इस समय तक जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल बचा होगा, वह लोकसभा चुनाव तक ही पूरा मान लिया जाएगा। वैसे भी आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा आयोग कराएगा। इस हेतु अनुच्छेद 325 में परिवर्तन करना होगा। साथ ही अनुच्छेद 324-ए में संशोधन करते हुए निगमों और पंचायतों के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ करा लिए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 368-ए के तहत इस संशोधन विधेयक को आधे राज्यों से भी पास करना जरूरी होगा। इसी अनुरूप केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है। गिनती शुरू हो जाती है। इस लिहाज से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए कम से कम 18 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग तक इस मुद्दे के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। यदि विपक्षी दल सहमत हो जाते हैं तो दो तिहाई बहुमत से होने वाले ये संशोधन कठिन कार्य

नहीं है। क्योंकि राजग के सहयोगी दल जदयू और तेलुगु देशम एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। बीजू जनता दल भी राजग के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। यदि संसद के अन्य विपक्षी दल, दलगत राजनीति से उपर उठकर देशहित में निर्णय लें तो यह विधेयक आसानी से दोनों सदनों से पारित हो जाएगा।

अनेक असमानताओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बंधा है। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्र को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देती है, जिससे भिन्न स्वभाव वाली राजनीतिक शक्तियों को केंद्रीय व प्रांतीय सत्ताओं में भागीदारी का अवसर मिलता है। नतीजतन लोकतांत्रिक प्रक्रिया गतिशील रहती है, जो देश की अखंडता व संप्रभुता के प्रति जवाबदेह है। देश में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी है। गोया, यदि बार-बार चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो मनुश्य का ध्यान बंटता है और समय व पूंजी का क्षरण होता है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रशासनिक शिथिलता दो-ढाई महीने तक बनी रहती है, फलतः विकास कार्य और जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। एक साथ चुनाव के चलते सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षाबलों को बार-बार चुनाव ड्यूटी के मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी।एक साथ चुनाव के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश प्रत्येक छह माह बाद चुनावी मूड में आ जाता है, लिहाजा सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में तो अड़चनें आती ही हैं, दूसरे नीतियों को कानूनी रूप देने में अतिरिक्तविलंब भी होता है। यह तर्क अपनी जगह जायज है। वैसे भी राजनीतिक दलों की महत्ता तभी है जब वे नीतिगत फैसलों को अधिकतम लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने सुझाव दें व उन्हें विधेयक के प्रारूप का हिस्सा बनाने के लिए नैतिक दबाव बनाएं। ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव का विचार कोई नया है। 1952 से लेकर 1967 तक चार बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ ही हुए हैं। इंदिरा गांधी का केंद्रीय सत्ता पर वर्चस्व कायम होने के बाद राजनीतिक विद्वेश व बेजा हस्तक्षेप के चलते इस व्यवस्था में बदलाव आना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी को विपक्ष की जो सरकार पसंद नहीं आती थी, उसे वे कोई न कोई बहाना ढूंढकर अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति से बर्खास्त करा देती थीं। नतीजतन मध्यावधि

देश प्रत्येक छह माह बाद चुनावी मूड में आ जाता है, लिहाजा सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में तो अड़चनें आती ही हैं, दूसरे नीतियों को कानूनी रूप देने में अतिरिक्त विलंब भी होता है। यह तर्क अपनी जगह जायज है।

चुनावों की परिपाटी पड़ती चली गई। इससे राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की बाध्यता निर्मित हो गई। अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त होने के बाद पीवी नरसिंह राव ने भी भाजपा शासित कई राज्य सरकारों को गिरा दिया था। वस्तुतः ऐसा अवसर आ गया कि देश में कहीं न कहीं चुनाव की डुगडुगी बजती रहती है। देश का कई करोड़ मतदाता किसी न किसी चुनाव की उलझन में जकड़ा रहता है।

चूंकि संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का उल्लेख तो है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ कराने का हवाला नहीं है। संविधान में इन चुनावों का निश्चित जीवनकाल भी नहीं है। वैसे यह कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होता है, लेकिन बीच में सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण या किसी अन्य कारण के चलते सरकार गिर या गिराई जा सकती है। केंद्रीय विधि आयोग ने 2018 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि पांच साल के भीतर यदि सरकार के भंग होने की स्थिति बने तो रचनात्मक अविश्वास मत हासिल किया जाए। मसलन, किसी सरकार को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य अविश्वास मत से गिरा सकते हैं, तो इसके विकल्प में जिस दल या गठबंधन पर विश्वास हो या जिसे विश्वास मत हासिल हो जाए, उसे बतौर नई सरकार की शपथ दिला दी जाए। कुछ विपक्षी दल एक साथ चुनाव के पक्ष में शायद इसलिए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर जिस किसी दल ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया तो केंद्र व ज्यादातर राज्य सरकारें उसी दल की होंगी? ये दल भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन हिंदुत्व की हवा से अधिक भयभीत हैं। पश्चिम बंगाल में एकतरफा जीत ने इनका भय और बढ़ा दिया है। ऐसे में यदि एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों का भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे सकता है।

बार-बार चुनाव की स्थितियां निर्मित होने के कारण सत्ताधारी राजनीतिक दल को भी यह भय बना रहता है कि उससे कहीं कोई ऐसा नीतिगत फैसला न हो जाए कि दल के समर्थक मतदाता नाराज हो जाएं? लिहाजा सरकारों को लोक-लुभावन फैसले लेने पड़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, स्वीडन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और फीलिपिंस ऐसे देश हैं, जहां एक साथ चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। गोया, भारत में भी यदि एक साथ चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ होती है तो केंद्र व राज्य सरकारें बिना किसी दबाव के देश व लोक हित में फैसले ले सकेंगी। सरकारों को पूरे पांच साल विकास व सुशासन को सुचारू रूप से लागू करने का अवसर मिलेगा। अतएव दलगत राजनीति से उपर उठकर सांसदों को देश हित में आत्मनिर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि इस विधि से धन की भी बड़ी बचत होगी।

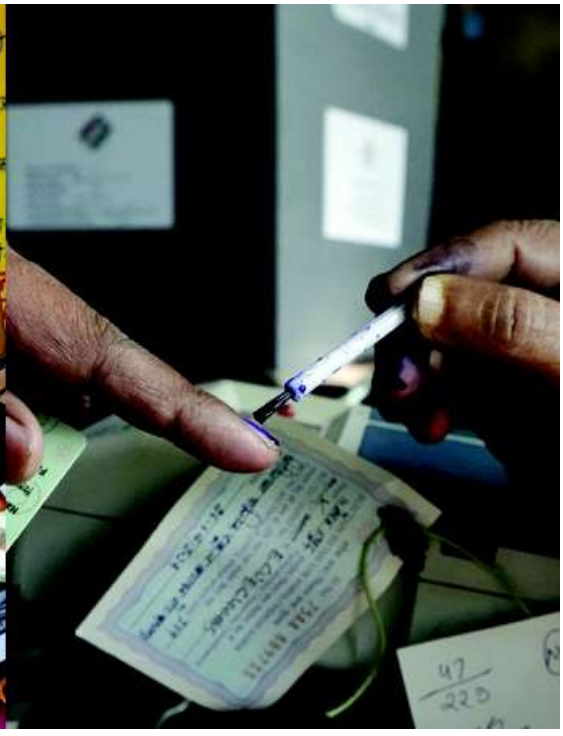

कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से अधिक सदस्य होने के निहितार्थ

डॉ. शैलेष शुक्ला

भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में कभी-कभी ऐसे प्रतीक अचानक उभरते हैं, जो देखने में भले व्यंग्य, मजाक या इंटरनेट ट्रेंड लगते हों, लेकिन उनके भीतर समाज की गहरी बेचैनी, निराशा और राजनीतिक असंतोष छिपा होता है। मई 2026 में सोशल मीडिया पर तेजी से उभरी काकरोच जनता पार्टी इसी प्रकार की एक घटना बनकर सामने आई है। कुछ ही दिनों में इस मंच से जुड़े लोगों और फॉलोअर्स की संख्या 02 करोड़ से अधिक हो गई है। यह अभियान एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन देखते-देखते यह व्यापक जनचर्चा का विषय बन गया। कई समाचार माध्यमों ने इसकी लोकप्रियता, युवाओं की भागीदारी और सोशल मीडिया पर इसके तीव्र विस्तार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी वास्तविक राजनीतिक दल बनेगी या नहीं। असली प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोग एक व्यंग्यात्मक नाम और प्रतीक के पीछे खड़े दिखाई देने लगे। किसी लोकतंत्र में जब जनता गंभीर राजनीतिक विमर्श की जगह व्यंग्यात्मक प्रतीकों में उम्मीद खोजने लगे, तो यह सामान्य राजनीतिक घटना नहीं होती।

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी वास्तविक राजनीतिक दल बनेगी या नहीं। असली प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोग एक व्यंग्यात्मक नाम और प्रतीक के पीछे खड़े दिखाई देने लगे। किसी लोकतंत्र में जब जनता गंभीर राजनीतिक

विमर्श की जगह व्यंग्यात्मक प्रतीकों में उम्मीद खोजने लगे, तो यह सामान्य राजनीतिक घटना नहीं होती। यह उस गहरी निराशा का संकेत होता है, जो लंबे समय से जनता के भीतर जमा होती रही है। बेरोजगारी, महँगाई, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असंवेदनशीलता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, चुनावी वादों की विफलता और संस्थाओं पर घटते भरोसे ने समाज के एक बड़े हिस्से को मानसिक रूप से थका दिया है। जनता अब केवल भाषण नहीं चाहती, वह जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहती है। लेकिन जब उसे लगातार एक जैसी राजनीति, एक जैसे आरोप-प्रत्यारोप और सत्ता संघर्ष ही दिखाई देते हैं, तब वह किसी नए प्रतीक की ओर आकर्षित होने लगती है, चाहे वह प्रतीक व्यंग्यात्मक ही क्यों न हो।

भारत की राजनीति में यह प्रवृत्ति नई नहीं है। कुछ वर्ष पहले आम आदमी पार्टी भी व्यवस्था विरोधी जनभावना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रोश के बीच उभरी थी। उस समय भी जनता पारंपरिक दलों से निराश दिखाई दे रही थी। लोगों को लगा कि शायद कोई नया राजनीतिक विकल्प व्यवस्था को बदल सकता है। दक्षिण भारत में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को लेकर भी युवाओं के बीच इसी प्रकार की उत्सुकता दिखाई दी। समय-समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में नए राजनीतिक प्रयोगों, क्षेत्रीय आंदोलनों और वैकल्पिक नेतृत्व के प्रति आकर्षण बढ़ता रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि भारतीय समाज के भीतर लगातार एक बेहतर विकल्प की तलाश जारी है। जनता किसी स्थायी वैचारिक बंधन में नहीं रहना चाहती। वह परिणाम चाहती है, पारदर्शिता चाहती है, सम्मानजनक जीवन चाहती है और सबसे

अधिक ईमानदारी चाहती है।

कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि भारत का एक बड़ा वर्ग वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर इस मंच के समर्थन में बड़ी संख्या में युवाओं, कलाकारों और सामान्य नागरिकों की सक्रियता यह दिखाती है कि असंतोष केवल राजनीतिक वर्ग तक सीमित नहीं है। कई रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया कि भारत के मुख्य न्यायधीश के

एक बयान के अगले दिन शुरू हुए इस डिजिटल अभियान के कुछ ही दिनों में इसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या प्रमुख राष्ट्रीय दलों के डिजिटल समर्थन से कहीं अधिक पहुँच गई। यह केवल इंटरनेट की सनसनी नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक स्थिति का संकेत है जिसमें जनता स्वयं को उपेक्षित, असहाय और राजनीतिक रूप से अप्रतिनिधित्वित महसूस कर रही है।

दरअसल कॉकरोच प्रतीक स्वयं में अत्यंत अर्थपूर्ण है। सामान्यतः काकरोच को ऐसी जीवित प्रजाति माना जाता है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहती है। संभवतः यही कारण है कि इस प्रतीक ने युवाओं और आम नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया। भारत का एक बड़ा मध्यम वर्ग, बेरोजगार युवा वर्ग, निम्न आय वर्ग और संघर्षशील समाज स्वयं को ऐसी ही परिस्थितियों में महसूस कर रहा है। लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सीमित अवसर, अस्थिर रोजगार, उँची शिक्षा लागत, महँगी स्वास्थ्य सेवाएँ और भ्रष्ट प्रशासनिक प्रक्रियाएँ लोगों को यह महसूस करा रही हैं कि वे केवल जी नहीं रहे, बल्कि किसी तरह बचे हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस आंदोलन से जुड़े कई संदेशों और प्रतिक्रियाओं में यही मनोविज्ञान दिखाई देता है कि जनता खुद को व्यवस्था के भीतर सम्मानित नागरिक नहीं, बल्कि संघर्षरत जीवित इकाई के रूप में महसूस कर रही है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र युवा वर्ग है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में शामिल है, लेकिन यही युवा आज सबसे अधिक असुरक्षा महसूस कर रहा है। सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या, निजी क्षेत्र में अस्थिर रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएँ, पेपर लीक, बढ़ती महँगाई और सामाजिक असमानता ने युवाओं में गहरी बेचैनी पैदा की है। जब युवाओं को यह महसूस होता है कि पारंपरिक राजनीतिक दल उनकी समस्याओं को केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रखते हैं, तब वे व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभिव्यक्तियों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसी अवधारणा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि राजनीतिक निराशा की डिजिटल अभिव्यक्ति बन गई। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास होता है। लेकिन यदि जनता लगातार यह महसूस करने लगे कि कोई भी राजनीतिक दल उसकी वास्तविक समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दे रहा, तो लोकतंत्र में व्यंग्य और अविश्वास का विस्तार होने लगता।

अमेरिका-ईरान युद्धः नई वैश्विक व्यवस्था की आहट

विवेकानंद माथने

21वीं सदी का वैश्विक परिदृश्य एक गहरे संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, जहाँ दशकों पुरानी एक ध्रुवीय व्यवस्था कमजोर पड़ रही है और शक्ति संतुलन तेजी से बहु ध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष इसी नई व्यवस्था की आहट है, जिसमें प्रभुत्व, संसाधनों और तकनीकी नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा लगातार तीव्र होती जा रही है। इस टकराव ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सूचना संप्रभुता को गहराई से प्रभावित किया है। अमेरिका के लिए यह संघर्ष केवल ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि अपनी वैश्विक स्थिति बनाए रखने का प्रश्न है। वह आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और कूटनीति के माध्यम से ईरान को नियंत्रित करने के साथ-साथ उभरते वैकल्पिक गठबंधनों को भी कमजोर करना चाहता है। यह प्रयास उस व्यवस्था को बनाए रखने का है, जिसमें अमेरिका केंद्रीय शक्तिरहा है। इजरायल लंबे समय से ईरान को अपने अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा मानता है। उसकी रणनीति केवल परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने तक नहीं, बल्कि क्षेत्र में अपनी सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखने पर केंद्रित है। वह ईरान समर्थित प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर कर क्षेत्रीय संतुलन अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है।

दूसरी ओर, ईरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बाहर निकलकर अपनी आर्थिक स्थिरता पुनः प्राप्त करना चाहता है। वह अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है और दावा करता है कि उसने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया। ईरान इजरायल के विरूद्ध अपनी सक्रियता को फिलिस्तीन के प्रति समर्थन के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। वह पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने वाले वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2024-25 में ईरान का चीन और रू स के साथ बढ़ता रणनीतिक सहयोग इस संघर्ष को वैश्विक आयाम देता है। चीन का बुनियादी ढांचे और उर्जा क्षेत्रों में निवेश तथा रूस का राजनीतिक समर्थन एक ऐसे गठजोड़ को

जन्म देता है, जो अमेरिकी प्रभाव को संतुलित कर सकता है। इसके विपरीत, अमेरिका की कोशिश ईरान को आर्थिक घेराबंदी के जरिए चीन और रूस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकालने की रही है।

2025 में सत्ता में वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने 'MAGA' के तहत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आयात-निर्यात शुल्कों और उर्जा संसाधनों पर एकाधिकार की रणनीति अपनाई। वेनेजुएला के बाद अब ईरान के

तेल भंडारों और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण की इस कोशिश नेक्षेत्रीय संघर्ष को वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व की लड़ाई में बदल दिया है। अमेरिकन यहूदी लॉबी और इजरायल ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ कड़ा रूख अपनाने के लिये दबाव बनाया। उनका तर्क रहा कि कूटनीति केवल ईरान को परमाणु शक्ति बनने का अवसर देती है, जो अंततः साझा हितों के विरूद्ध होगी। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य घेराबंदी, सुरक्षा समझौते और इजरायल की तकनीकी श्रेष्ठता का मुख्य उद्देश्य ईरान को कमजोर कर क्षेत्रीय वर्चस्व बनाए रखना है।

जून 2025 में, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम और लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाने हेतु समझौता अंतिम चरण में था, तभी इजरायल ने अचानक हमला कर कूटनीति की संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया। इस 12 दिवसीय युद्ध में अमेरिका ने इजरायल का समर्थन करते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों को अपना मुख्य निशाना बनाया।

इस सैन्य कार्रवाई के दस महीने बाद पुनः हुए अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ-साथ नागरिक ठिकानों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 168 मासूम बच्चों की मौत हुई। इस अमानवीय कृत्य ने जहाँ विश्व भर में आक्रोश पैदा किया और इसे वैश्विक स्तर पर युद्ध अपराध के रूप में देखा गया, वहीं नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। युद्ध के कारण तेल की कीमतों में आए भारी उछाल ने दुनिया को यह अहसास करा दिया कि उर्जा के लिए दूसरों पर निर्भरता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिससे उर्जा सुरक्षा का प्रश्न वैश्विक बहस के केंद्र में आ गया। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने इजरायल की तकनीकी श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ते हुए अमेरिका को इस युद्ध मोर्चे पर विफल और असहाय सिद्ध कर दिया।

इस संघर्ष में पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ डिजिटल औपनिवेशिक ताकतों ने ईरान के बुनियादी ढांचे और बैंकिंग प्रणाली को निष्प्रभावी बनाने के लिए साइबर हमलों का सहारा लिया। उन्नत एल्गोरिदम और तकनीकी प्रभुत्व के माध्यम से सूचना संप्रभुता को चुनौती दी गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आधुनिक विश्व व्यवस्था में केवल सैन्य ताकत ही

नहीं, बल्कि तकनीकी और सूचना पर नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

युद्ध के दौरान कई देशों ने डॉलर के प्रभुत्व से हटकर वैकल्पिक मुद्राओं का उपयोग शुरू किया, जिससे अमेरिका की आर्थिक दबाव बनाने की क्षमता कमजोर हुई। इसी क्रम में ब्रिक्स (BRICS) के विस्तार और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों के प्रति बढ़ते झुकाव ने एक बहुध्रुवीय आर्थिक ढांचे को और मजबूत किया है, जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन का संकेत है। इन स्थितियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख को कमजोर कर दिया है, जिसके बल पर वह दशकों से राज कर रहा था।

अमेरिका की एकतरफा नीति से नाटो के भीतर मतभेद उभर आए और कई सदस्य देशों ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। इससे नाटो की एकता कमजोर हुई। अमेरिका के भीतर भी जनता ने इस युद्ध का विरोध किया, जबकि ईरान की जनता अपने देश के समर्थन में एकजुट रही, जिससे अमेरिका की वैश्विक छवि को गहरा आघात पहुंचा।

यह संघर्ष एक बुनियादी प्रश्न खड़ा करता है कि अमेरिका को दुनिया का स्वयंभू रक्षक बनने का अधिकार किसने दिया। आज भी कई संप्रभु राष्ट्र अमेरिकी सामरिक और आर्थिक आतंक के साये में जीने को मजबूर हैं। अमेरिका का यह भारी दबाव अन्य देशों को उसकी गलत नीतियों का विरोध करने से रोकता है,जो भय की राजनीति को प्रबल कर वैश्विक संतुलन को कमजोर कर रहा है। शक्ति के बल पर कमज़ोरों को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन स्थायी शांति दमनकारी नीतियों या सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि केवल न्याय से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि इस उभरती व्यवस्था को न्याय और समानता का आधार नहीं मिला, तो यह पुराने शोषणकारी प्रभुत्व का ही एक नया रूप बनकर रह जाएगी। ऐसे में वर्तमान संघर्ष नई वैश्विक व्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

भविष्य की विश्व व्यवस्था को दमनकारी वर्चस्व के बजाय न्यायपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता है। विश्व के राष्ट्रों को भय की राजनीति से बाहर निकलकर सहयोग और न्याय पर आधारित एक नया तंत्र विकसित करना होगा। तभी मानवता ऐसे विनाशकारी संघर्षों से मुक्त होकर एक सुरक्षित और समतामूलक भविष्य की ओर बढ़ पाएगी।

वैभव सूर्यवंशीः भारत का उभरता क्रिकेट सितारा

क्रिकेट, भारत का प्रिय खेल, हमेशा नई प्रतिभाओं के लिए तैयार रहता है। हर पीढ़ी कुछ ऐसे खिलाड़ियों को सामने लाती है जो न केवल अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से अलग पहचान बनाते हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। ऐसे ही एक उभरते हुए सितारे का नाम है वैभव सूर्यवंशी। उनकी यात्रा, शैली और समर्पण ने उन्हें भारतीय क्रिकेट की नई आशा बना दिया है। वैभव सूर्यवंशी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही उनमें क्रिकेट के प्रति गहरी रूचि और जुनून था। उनका परिवार हमेशा उनके खेल के प्रति उत्साहित और सहायक रहा। वैभव का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें अन्य बच्चों से अलग बना दिया। छोटे स्तर पर उन्होंने कई स्थानीय टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा। उनके शुरूआती कोच ने हमेशा उनकी तकनीक और मानसिक दृढ़ता की तारीफ की। वैभव की यह खासियत थी कि वह केवल अपनी तकनीक पर ही ध्यान नहीं देते थे, बल्कि खेल की समझ और मानसिक रणनीति पर भी लगातार काम करते थे। वैभव सूर्यवंशी का भविष्य बेहद उज्ज्वल दिखाई देता है। अगर वह अपने खेल को लगातार सुधारते रहें और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते रहें, तो वह भारतीय क्रिकेट का एक प्रमुख हिस्सा बन सकते हैं। उनके पास केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि नेतृत्व की संभावनाएँ भी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते समय उनके प्रदर्शन और अनुभव से भारत को नई मजबूती मिल सकती है। वह युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं और भारतीय क्रिकेट के भविष्य को नई उँचाइयों तक ले जा सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी का जीवन केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। वह अपने परिवार और समुदाय के प्रति जिम्मेदार हैं। उनकी विनम्रता, अनुशासन और मेहनत ने उन्हें न केवल एक महान खिलाड़ी, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बनाया है। उन्होंने कई युवाओं को क्रिकेट की ओर प्रेरित किया है। उनकी यात्रा यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत, धैर्य और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपनी मंजिल हासिल कर सकता है।

वैभव सूर्यवंशी भारत के क्रिकेट में एक नई उम्मीद की किरण हैं। उनकी यात्रा, संघर्ष और उपलब्धियाँ यह दर्शाती हैं कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्वल है। घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल और राष्ट्रीय टीम तक का उनका सफर युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह केवल बल्लेबाज नहीं हैं, वह रणनीतिकार, धैर्यशील खिलाड़ी और टीम का मजबूत स्तंभ हैं। उनके समर्पण और खेल के प्रति जुनून ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक उज्ज्वल सितारे के रूप में स्थापित किया है। वैभव सूर्यवंशी का नाम आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका सफर यह साबित करता है कि सही दिशा में मेहनत और समर्पण से कोई भी खिलाड़ी अपने सपनों को साकार कर सकता है।

क्रिकेट में शुरूआत

वैभव सूर्यवंशी ने अपना पेशेवर करियर घरेलू क्रिकेट से शुरूकिया। उन्होंने मुंबई के अंडर-19 और फिर रणजी ट्राफी जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। शुरूआत में ही उनकी बल्लेबाजी की शैली ने दर्शकों और विशेषज्ञों का ध्यान खींचा। उनका धैर्य, शानदार स्ट्रोक प्ले और मैच के दबाव में शांत रहकर खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वैभव एक तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं। उनके खेल की खासियत उनकी कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और डिफेंस की बेहतरीन तकनीक है। साथ ही, वह गेंदबाजी में भी कुछ हद तक योगदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक बहुमुखी खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है।

घरेलू क्रिकेट में उपलब्धियाँ

वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने रणजी ट्राफी, विजय हजारे ट्राफी और सैयद मुश्ताक अली ट्राफी जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी बल्लेबाजी हमेशा टीम के लिए स्थिरता और मजबूती लेकर आई। रणजी ट्राफी में उनके कई शतक और अर्धशतक ने मुंबई को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उन्होंने न केवल बड़े स्कोर बनाए, बल्कि मैच के निर्णायक क्षणों में भी शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इन उपलब्धियों ने उन्हें राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजरों में ला दिया।

How Kanshi Ram's slogans became the gospel for the masses

Ritesh Jyoti

In every human civilizational struggle, slogans have been an effective means of awakening mass consciousness. Just a handful of words that speak to a million hearts and bring them together. They travel from pamphlets and rallies to houses and villages and from streets to the farthest corners of a country.

Manyavar Kanshi Ram had the knack of mobilizing the masses with slogans, bringing everyone on the same page and breathing life into the movement. The Phule-Ambedkar mission acquired a sense of purpose and made the most deprived, the harassed, the victims of the caste system believe that they could one day become the Hukmaran (the ruler) of the country. Beyond the immediate purpose the slogans served, they became a blueprint for the Bahujan movements to come.

Kanshi Ram created a new language in Indian politics that exposed the false majority of Hindu nationalism facilitated by Gandhi. Kanshi Ram understood the threat of communal majority to a nation, for Dr Ambedkar had written years earlier in Thoughts on Linguistic States: “People who rely upon majority rule forget the fact that majorities are of two sorts: (1) Communal majority and

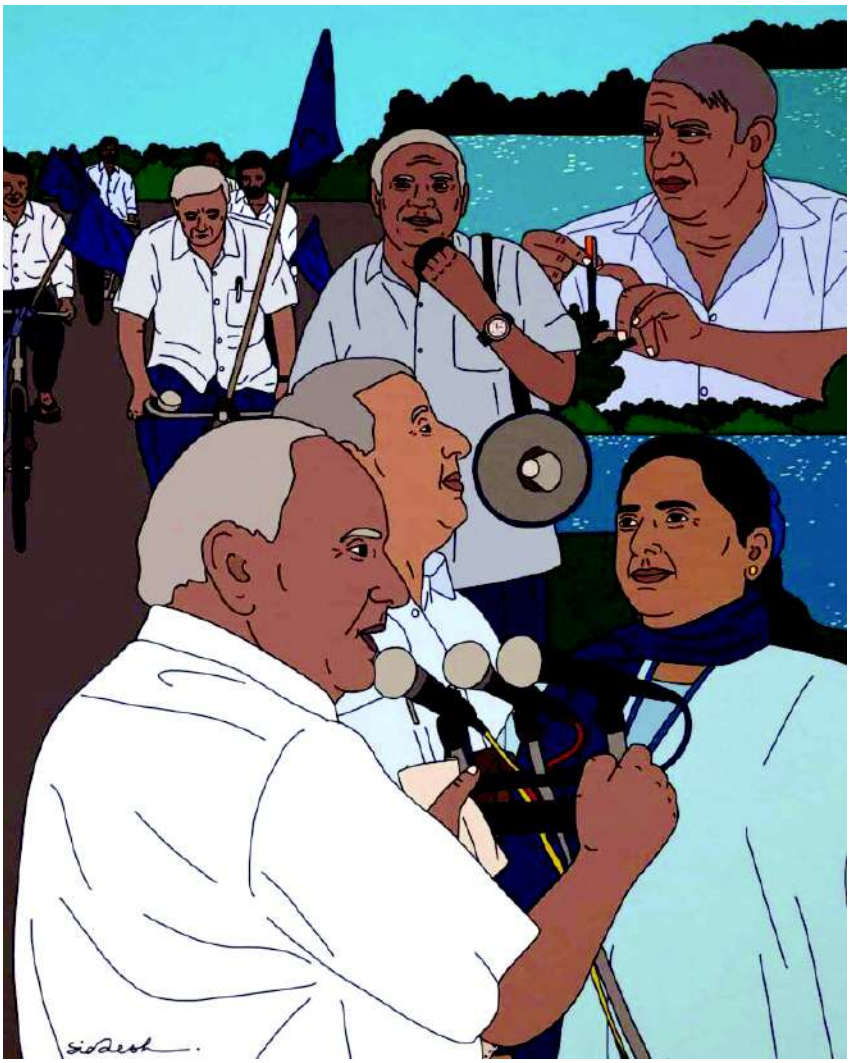

(2) Political majority. A political majority is changeable in its class composition. A political majority grows. A communal majority is born. The admission to a political majority is open. The door to a communal majority is closed. The politics of a political majority are free to all to make and unmake. The politics of a communal majority are made by its own members born in it. How can a

communal majority run away with the title deeds given to a political majority to rule? To give such title deeds to a communal majority is to establish a hereditary Government and make the way open to the tyranny of that majority. This tyranny of the communal majority is not an idle dream. It is an experience of many minorities."

Kanshi Ram had in hand the massive task of creating a political majority which could counter this communal majority, which he articulated in his vision for a Bahujan Samaj. It was almost impossible to create a political majority out of thousands of castes and sub-castes, who do not share any corporate sentiment or a common purpose. However, Kanshi Ram made it happen in Uttar Pradesh, the first laboratory of communal majority.

His formula was N*D*S=C (Need into Desire into Strength=Change). The need was already there unserved for centuries; the desire had been created by the provisions in the Constitution whose drafting Ambedkar had overseen and the struggles of the Untouchables he had led, as well as the struggles of the Shudras and Adivasis both before and after Independence in different parts of the country. For strength, Kanshi Ram asked for three Ts from the beneficiaries of the Phule-Ambedkarite movement Time, Treasure and Talent. He would say in his cadre camps that at least one of the Ts should be volunteered by the middle class that has been created as a result of the Phule-Ambedkite Movement.

His profound slogans played a decisive role in awakening the chetana (political consciousness) in the Dalit, Shoshit (exploited) Samaj.

In the First World Dalit

Convention that was held in Malaysia in 1998, Manyavar Kanshi Ram said: "… I know fully well that there are 45 lakh hectares of land under plough and more than that land is available in India which can be brought under plough but nobody has given that land to us and nobody will give. Why? Because of Brahmanical social order in India. For that reason only they have created the caste. That there should be some castes who possess land and there should be other castes who should plough the land. In the interests of those people who are the victims of the caste system we must do something, something which can do the needful for them."

The community began to realize that if they wanted to rid themselves of the degraded caste occupations imposed upon them and stop living at the mercy of landowning castes, they needed land of their own. They understood that no one would hand it to them; it was upon them to claim it.

While addressing a cadre camp, Kanshi Ram said:

"I gave a slogan to the toiling, landless masses of the Scheduled Castes in North India: 'Jo Zameen Sarkari Hai, Wo Zameen Hamari Hai'. We kept asserting this slogan until we formed the government in Uttar Pradesh."

Later, when the government was formed in Uttar Pradesh under Mayawati, the slogan became the state's slogan. Nearly seven lakh acres of land had been allotted to Scheduled Castes on paper by previous governments.

What Mayawati did- as Kanshi Ram emphasised in that speech- was to ensure its actual distribution on the ground. She issued strict instructions to district collectors to swiftly dispose of pending land allotments in favour of Scheduled Caste communities. In effect, the movement's slogan became the working slogan of the administration: "Jo Zameen Sarkari Hai, Wo Zameen Tumhari Hai". Kanshi Ram had said to Mayawati that she had to do the work of 6 years in 6 months.

"Vote se lenge CM-PM, Arakashan se lenge SP-DM" (We will use votes to become CM and PM and use reservation to become SP and DM.) The slogan was basically what Dr Ambedkar articulated in his SCF manifesto: "The Constitution of Free India has made the Backward Classes, the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes virtually the masters of the country." Kanshi Ram saw it as a weapon waiting to be used. He understood that if the Bahujan truly acted as a political majority, they would cease to be victims and become masters. If "Jo Zameen Sarkari Hai, Wo Zameen Hamari Hai" reclaimed economic dignity, then "Vote se lenge CM-PM, Arakshan se lenge SP-DM" exhorted the Bahujan to capture State power. Through the ballot, Kanshi Ram urged the Bahujan to secure political leadership; through reservation, to enter the administrative machinery. The prime minister and chief minister make policies and decisions, while the SP and DM implement and enforce them on the ground. The slogan became the doctrine for the masses for their upliftment under the constitution framework.

Another similar slogan was "Jiski Jitni Sankhya Bhari, Uski Utni Hissedari" (those who are more in number must have a proportionate share in governance, employment, education and resources).

Kanshi Ram raised a banner against liquor consumption which, as Dr Ambedkar said in the Scheduled Castes Federation (SCF) Manifesto, "It [liquor] has produced more crime and is the worst soil of demoralization of the lower classes." He gave the slogan, "Savarno ke basti mein school aur davakhane, Dalito ke basti mein sharabkhane- nahi chalega, nahi chalega" ("schools and hospitals in upper-caste localities, liquor shops in Dalit localities- this will not be tolerated, this will not be allowed").

A giving society is a ruling society. For centuries, the Bahujan had been pushed into a position where they were forced to demand rights, seek concessions, and struggle merely for survival. Kanshi Ram wanted to reverse that condition. He did not want a community that survives on appeals; he envisioned a society that produces, governs, and gives direction.

Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti (DS4), the predecessor of the Bahujan Samaj Party (BSP), had also campaigned against this structural violence by taking out cycle yatras in Scheduled Caste hamlets to curb the evil of alcohol abuse and to prevent the opening of liquor shops in these localities. Kanshi Ram received a great deal of support from Scheduled Caste women for this initiative.

One of Kanshi Ram's frequent reminders in his speeches was: "Humein lene nahi, dene wala samaj banna hai" (We must become a giving society, not a taking one.)

A giving society is a ruling society. For centuries, the Bahujan had been pushed into a position where they were forced to demand rights, seek concessions, and struggle merely for survival. Kanshi Ram wanted to reverse that condition. He did not want a community that survives on appeals; he envisioned a society that produces, governs, and gives direction.

To him, power was not only about securing a share in the State, but about becoming capable of shaping the State itself.

It is time we revived these slogans in our political spheres, in our social spaces and university corridors and connected with villages, bastis and working-class neighbourhoods. Kanshi Ram's slogans remind us that politics must be spoken in a language that awakens and organizes the masses and provides them a blueprint to start their own movements.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

बी.एस.सी. मास कम्यूनिकेशन (3 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671 संतोष गुप्ता - 9755618891

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

रेल विकास को मिल रही डबल इंजन की रफ्तार

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

₹ रेल बजट

₹6,900 करोड़ (2025-26)

10 वर्षों में 22 गुना वृद्धि

R.O. No. 13772/24

सुशासन का संकल्प

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सशक्त धर्म समृद्ध संस्कृति

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

60+ आयु वर्ग

दिव्यांगजन, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रदेश के बाहर तीर्थों की निःशुल्क यात्रा

श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना

37,000

से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ की निःशुल्क यात्रा

शक्तिपीठ परियोजना

राज्य के 5 शक्तिपीठों

के विकास हेतु **₹5 करोड़** का प्रावधान

R.O. No. 13772/24

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in